असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा वृहस्पतिवार, तिथि 02 मार्च, 2023 ई0
अष्टम सत्र 11 फाल्गुन, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण कार्य मंत्रणा...

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट रूक जाइये...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मजदूरों पर हमला हुआ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता आप जरा एक मिनट, आप बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज प्रथम पाली की बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी । समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय...

अध्यक्ष : आप से पहले माननीय सदस्य सत्यदेव राम बोल रहे हैं...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, नेता प्रतिपक्ष की प्राथमिकता होती है ।

अध्यक्ष : उसके बाद आप बोल लीजियेगा । एक मिनट कुछ कहेंगे वे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बहुत कम बात है कि कल भोजनावकाश के बाद माननीय सदस्य संजय सरावगी ने सदन के अंदर उन्होंने कुछ बातें कही है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये न ।

श्री सत्यदेव राम : यह सबको कहने का अधिकार है

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री सत्यदेव राम : लेकिन मैं आपत्ति करता हूं कि इन्होंने कहा कहां गया महबूब...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री सत्यदेव राम : यह मर्यादा के खिलाफ है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह जी आप बैनर नीचे रखें ।

श्री सत्यदेव राम : और यह साबित करता है कि ये जमींदारी भाषा में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैनर रखें ।

श्री सत्यदेव राम : बात करते हैं तो यह जान लें कि हम जमींदारी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैनर न दिखावें, बैनर को नीचे रखें ।

श्री सत्यदेव राम : यह जमींदारी भाषा सदन के अंदर नहीं चलेगी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह आसन का आदेश है कि बैनर आप न दिखावें, बैनर नीचे रखें ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय सदस्यों की गरिमा मत गिराइये । राजनीति की जितनी बातें करनी हो आप करिये लेकिन सदस्यों की गरिमा को आप नहीं गिरा सकते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सत्यदेव राम : इस बात पर संजय सरावगी सदन के अंदर माफी मांगें और उस आपत्तिजनक बात को प्रोसिडिंग से निकाला जाय ।

अध्यक्ष : सत्येदव राम जी आप बैठ जाइये आप कह दिये जो कहना था, अब नेता विरोधी दल अपनी बात रखेंगे । नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा बनाये रखने के लिये सबको संयम की जरूरत है और हमलोगों की अनुपस्थिति में अगर कोई माननीय सदस्य हमलोगों की तरफ इशारा करके कितने शब्दों का गाली के बतौर उन्होंने उपयोग किया है । महोदय, क्षमा मंगवानी चाहिये महबूब जी को और इस तरह की परंपरा कतई नहीं बढ़ने देनी चाहिये और आसन से तो उसी समय एक्शन लेना चाहिये, इसको निकालना चाहिये । लेकिन महबूब जी जो कहे और उसके बाद यह शब्द नहीं हटा जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह का वातावरण बन रहा

है । ये सदन के लिये कतई उचित नहीं है । अगर जो प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों को प्रतिष्ठा देने का भी ध्यान रखें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज राज्य में 78 लाख स्नातक बेरोजगार हैं और इंटर मैट्रिक उत्तीर्ण की संख्या 2 लाख 98 हजार है जो रोजगार की तलाश में हैं । बी0पी0एस0सी0 में 49 हजार, बी0टी0एस0 में 12 हजार, बी0एस0एस0सी0 में 4 हजार...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष आपको...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं जो कहना चाह रहा हूं आज राज्य में साढ़े चार लाख शिक्षक अभ्यर्थी और चार हजार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का मामला अटका है...

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सुन लिया जाय । महोदय, आज इतने बेरोजगार, एक मिनट सुना जाय महोदय, इतने बेरोजगारी के बाद आज हमारे लोग जाते हैं बाहर में और किस तरह से तमिलनाडु के अंदर उनको पीटा गया, किस तरह से संज्ञान नहीं लिया गया सरकार से और यहां से उप मुख्यमंत्री...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : जाकर के उसके जन्मदिवस पर पिकनिक मना रहे हैं उसी तमिलनाडु में यह कतई उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता जब आसन पर बैठते थे तब बिहार विधान सभा के कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते थे और आज मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से कि किस नियम का हवाला देकर सदन में दूसरी बात उठा रहे हैं जिसका समय नहीं है । अभी तो अल्पसूचित प्रश्न का समय है, तारांकित प्रश्न का समय है, ध्यानाकर्षण का समय आयेगा । इस तरह के प्रश्न को अगर उठायेंगे नेता विरोधी दल तो सदन का समय बर्बाद होगा और जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है, तारांकित, अल्पसूचित प्रश्न है, उनका समय भी खराब होगा । तो माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह से आप नियम का वॉयलेंस नहीं करें, नियम को तार-तार नहीं करेंगे, यह अनुरोध करना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं बड़े अनुभवी हैं, बड़े ज्ञानी हैं । इनको जानकारी होनी चाहिये कि कार्यस्थगन जो दिया गया है वह मुद्दा ज्यादा ज्वलंत है तो प्रश्न के पहले उस पर चर्चा होती है । कहां भूल गये

वे, लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहे तो भूल गये और यह नियमावली के तहत है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आसन स्वीकृति नहीं देता तो उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आग्रह करने का लोकतंत्र में अधिकार है मेरा, 98 के तहत ये नियमावली का अधिकार है महोदय और...

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल आज आपका भी अल्पसूचित प्रश्न है इसलिये प्रश्न को चलने दिया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, अल्पसूचित से ज्यादा ये नियुक्ति का मामला और पेपर लीक का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है...

अध्यक्ष : कहां से कहां लेकर जा रहे हैं...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, प्रतिभा का हनन हो रहा है, पूरे बिहार के बेरोजगार नौजवान पलायन के लिये विवश हैं । महोदय, इस पर चर्चा पहले हो ।

अध्यक्ष : माननीय आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : इस पर चर्चा पहले हो महोदय ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष से मैं कह रहा हूं कि आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आप ज्वलंत विषय पर चर्चा...

अध्यक्ष : श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न में आपको जवाब प्राप्त है आप पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया है तो मैं भी उस पर बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, जिस तरह माननीय सदस्य महबूब आलम ने...

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें ।

श्री संजय सरावगी : भाजपा के विधायकों को फलां की औलाद, फलां की औलाद, फलां की औलाद कहकर जो संबोधित किया, उनको माफी मांगना चाहिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जय प्रकाश यादव ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । आपको मैंने पुकारा और आप अन्य बातों को कहने लगे । नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को ऑर्डर में लाना आपकी जिम्मेवारी है और जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग व्यवधान डालकर के सदन को अव्यवस्थित कर रहे हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि सदन चले । प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, निर्धारित जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आपने ही तोड़ने का काम किया है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सत्ताधारी दल के लोग बाधित कर रहे हैं, यह उचित कतई नहीं है और इस तरह से सेना का अपमान करने वाले मंत्री बैठकर जवाब देते हैं उनको रोक देते हैं, कभी श्री महबूब आलम गालियों की बौछार करते हैं सदन के अंदर उनका पीठ थपथपाया जाता है । इस तरह से सदन के अंदर, बिहार के अंदर एक भय का वातावरण बनाने का, नकारात्मक वातावरण बनाने का खेल नहीं चलेगा । महोदय, ज्वलंत विषय पर चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

(व्यवधान)

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप कृपया पोस्टर को नीचे करें । आप क्या प्रश्नकाल को कभी चलने नहीं देना चाहते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-2/राहुल/02.03.2023

अध्यक्ष (क्रमशः) : आपके क्षेत्र के सवाल नहीं हैं, नियम कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं । यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला माननीय विरोधी दल आपके द्वारा है इसलिए आप बैनर को नीचे रखें...

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-358 (श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक ।

(व्यवधान जारी)

3. नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन के साथ-साथ शहर की साफ-सफाई का कार्य कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इंटिग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैंनेजमेंट के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निष्पादन हेतु पी0पी0पी0 मोड़ में परियोजना की परिकल्पना की गई है...

(व्यवधान जारी)

बिहार राज्य के 161 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 24 क्लस्टर में विभाजित किया गया है । इसके अन्तर्गत बेतिया क्लस्टर में नगर निगम, बेतिया को अग्रणी नगर निकाय के रूप में रखा गया है जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु Material Recovery Facility, Refuse Derived Fuel, Window Composting, Compost Plant एवं Scientific Landfill Site बनाने का प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में है...

(व्यवधान जारी)

उल्लेखनीय है कि सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत सभी शहरों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्मॉर्ट वाटर ड्रेनेज निर्माण कराने की योजना है । संबंधित नगर निकायों में जल निकासी हेतु उपलब्ध राशि के आलोक में योजना का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरांत कराया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है...

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : कोई स्पष्ट जवाब नहीं है महोदय । ये सीधे तौर पर गोलमटोल बातें हैं । बेतिया अभी सबसे प्रदूषित शहरों में गिना गया...

(व्यवधान जारी)

वहां पर न कूड़ा कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है और न वहां नालियों के पानी निकासी और वहां के सड़न को रोकने की व्यवस्था है । यह जो गोलमटोल जवाब दिया गया है हम साफ माननीय मंत्री जी से सरकार से यह चाहते हैं कि साफ-साफ यह स्पष्ट हो कि क्या वह वर्ष 2023-24 के वित्तीय सत्र में वहां यह काम होगा या नहीं होगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार समग्र रूप से पूरे बिहार के नगर निकायों के माध्यम से वहां जो ड्रेनेज प्रॉब्लम है या जो कुछ भी समस्या इस प्रश्न के अंदर उठायी गयी है, सोलिड बेस्ट मैंनेजमेंट से लेकर तमाम सारी चीजों का कार्यान्वयन करेगी और इसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया जारी है और उसमें बेतिया को अग्रणी नगर निकाय के रूप में रखा गया है।

(व्यवधान जारी)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो कह रहे हैं बात वही की वही रह गई वित्तीय वर्ष 2023-24 के सत्र में वे स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, नहीं जवाब आ रहा है हम इस पर साफ-साफ यह कहना चाहते हैं कि कल लोकतंत्र जो यहां शर्मसार हुआ...

(व्यवधान जारी)

कि कोई विधान सभा का सदस्य यदि विधान सभा में अपना वक्तव्य दिया है तो उसको कोई इस ढंग से अपराधियों की भाषा में आकर के धमकी देगा कि कहां है महबूब आलम, कहां है महबूब आलम । यह लोकतंत्र का अपमान है और विधान सभा का अपमान है और इस...

(व्यवधान जारी)

लिहाज से यह हम समझते हैं कि विधान सभा को संजय सरावगी जो माननीय विधायक हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए । यह पूरे तौर पर गरीबों को ये भाजपा के लोग धमकी देते हैं,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अल्पसंख्यकों को धमकी देते हैं उसी ढंग से यहां पर आकर के ये धमकी दे रहे हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : इन पर कार्रवाई होनी चाहिए । हम यह मांग करते हैं और पूरा सदन इस पर कार्रवाई करें कि विधान सभा में, लोकतंत्रीय संस्था में धमकी देना कहां तक सही है यह गरीबों के साथ, महबूब आलम पूरे बिहार के गरीबों के नेता हैं...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,..

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : दलितों के नेता हैं, अल्पसंख्यकों के नेता हैं और...

अध्यक्ष : यह क्या आप कह रहे हैं...

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : उनके साथ अपमानजनक कार्रवाई की जा रही है । यहां लोकतंत्र के मंदिर में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि कार्रवाई शुरू है, कार्रवाई हो रही है, आने वाले वित्तीय वर्ष में उस पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जायेगा और आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सरकार ने दिया है, आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या-359 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र संख्या-147, बखरी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता, बेगूसराय से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा सुग्गा,...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : ये पोस्टर को आप लोग लीजिये, पोस्टर लीजिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : थाना नं0-266 के अंतर्गत वर्ष 2010 में 235 भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित भूमि की जांचोपरांत पाया गया कि वर्ष 2010 में मौजा-सुग्गा, थाना नं0-266 में कुल 235 भूमिहीन महादलित परिवारों को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाने के कारण महादलित विकास योजना अंतर्गत क्रय नीति के तहत प्रति परिवार 03 (तीन) डिसमिल भूमि उपलब्ध करायी गयी थी...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सरकार के सामने आप खड़े हुए हैं कृपया आप अपनी जगह पर जाइये, उस स्थान से हटें । आप ट्रेजरी बेंच के पास खड़े हैं आप हटिये । आप अपनी जगह पर जाइये, ट्रेजरी बेंच के पास आप नहीं खड़े हो सकते हैं...

(व्यवधान जारी)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, जिसमें से लगभग 15-16 परिवार मौजा-चक्की, थाना नं0-272 के हैं तथा शेष सभी मौजा-सुग्गा के मुशहरी टोला के परिवार हैं । भूमि क्रय किये जाने के उपरांत सभी लाभुकों के नाम दाखिल-खारिज कर उनकी जमाबंदी संधारित की जा चुकी है स्थल...

(व्यवधान जारी)

स्थल जांच के क्रम में पाया गया कि क्रय नीति के तहत उपलब्ध करायी गयी भूमि पर वर्तमान में गेहूं की फसल लगी है । जांच के क्रम में यह भी

पाया गया कि लगभग 150 परिवारों का स्थल पर दखल-कब्जा है । गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत शेष लगभग 85 परिवारों को यथाशीघ्र दखल दिलाने की कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, मेरा पूरक है । जो जवाब दिया गया है वह गलत जवाब है । हम समझते हैं कि माननीय मंत्री जी को अंचल अधिकारी, बखरी पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कहते-कहते थक गये हम लोग वह जो जमीन दी गई है सरकार के द्वारा खरीदकर के अभी तक उस जमीन पर लोगों को दखल कब्जा नहीं दिया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने कार्रवाई करने के लिए आपके प्रश्न का जवाब देते समय उन्होंने कहा है फिर भी मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी...

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, गेहूं की कटाई के बाद सारे लोगों को वहां बसा दिया जायेगा ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, वह गलत रिपोर्ट आपको दिये हैं, जगह खाली है, बखरी सी0ओ0 गलत रिपोर्ट दिये हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार आपकी सूचना को ग्रहण करती है और इन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे । आप अपना स्थाना ग्रहण करें ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-360 (श्री आनन्द शंकर सिंह, क्षेत्र संख्या-223, औरंगाबाद)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के जम्होर ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से वर्तमान में वार्ड संख्या-02 एवं 03 में सीधी जलापूर्ति के माध्यम से हर घर नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष वार्डों यथा-5,7,11,12 एवं 13 में जलापूर्ति हेतु योजना तैयार कर ली गई है जिसकी स्वीकृति उपरांत कार्य कराया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : महोदय, जवाब दिया गया है कोई पूरक प्रश्न है तो माननीय सदस्य पूछें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : माननीय मंत्री जी सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल, हर घर जल योजना । मैं यह पूछना चाहता हूं कि गर्मी आने वाली है और पेयजल का संकट उत्पन्न होने वाला है, कब तक इन वार्डों में आप पानी पहुंचा देंगे...

(व्यवधान जारी)

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, योजना तैयार है और जून, 2023 तक, इसी तीन माह के बाद कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अख्तरूल ईमान साहब, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-3/मुकुल/02.03.2023

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-361(श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र सं0-56, अमौर)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित) : (1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बैसा प्रखण्ड में पूर्व से कार्यभारित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में किए जाने के फलस्वरूप बैसा प्रखण्ड में हुई रिक्ति के कारण उक्त प्रखण्ड के सहकारिता संबंधी कार्य प्रभावित न हो, के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, पूर्णियां अंचल, पूर्णियां के आदेश ज्ञापांक-122, दिनांक-12.11.2022 द्वारा निकटवर्ती अमौर प्रखण्ड में कार्यभारित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को बैसा प्रखण्ड में अतिरिक्त रूप से कार्यभारित किया गया था ।

पुनः सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, पूर्णियां अंचल, पूर्णियां के आदेश ज्ञापांक-48, दिनांक-23.02.2023 द्वारा श्री आशित अजीत, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, पूर्णियां को बैसा प्रखंड में पूर्णकालिक रूप से कार्यभारित किया गया है ।

(2) उपरोक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) उपरोक्त खण्ड में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न करने के बाद प्रखंड बैसा में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को बहाल कर दिया है, पदस्थापन कर दिया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा है कि यहां पर जब क्वैश्चन होता है तो काम होता है, इसलिए ऐसे वक्त में सदन

की अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए सदन साल में 30-35 दिन नहीं, बल्कि बड़ा कराइये । इससे हमलोगों का बहुत काम हो जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-362(श्री अशोक कुमार, क्षेत्र सं0-132, वारिसनगर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक ।

अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर के प्रतिवेदनानुसार खानपुर अंचल के मौजा-चतुर बहुआरा, थाना नं0-197, की भूमि का दाखिल-खारिज एवं खरीद-बिक्री सामान्य रूप से होती है । हल्का कार्यालय में उक्त मौजा का आर0एस0 खतियान एवं जमाबंदी पंजी-2 संधारित है । दाखिल-खारिज एवं भूमि के खरीद-बिक्री में रैयतों को कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है । अगर उसके बावजूद कोई कठिनाई नजर आती है तो माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से मुझे लिखकर दें कि किन-किन लोगों की तो मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगा ।

श्री अशोक कुमार : धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-363(श्री दिलीप राय, क्षेत्र सं0-26, सुरसंड)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-364(श्री बीरेन्द्र कुमार, क्षेत्र सं0-139, रोसड़ा (अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-365(श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र सं0-25, परिहार)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती गायत्री देवी ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-366(श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-367(डॉक्टर संजीव कुमार, क्षेत्र सं0-151, परबत्ता)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित): (1) वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पंचायत, परबत्ता को षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि तीन करोड़ तिरसठ लाख चौबीस हजार एक सौ छत्तीस रुपये मात्र प्राप्त हुआ है ।

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, परबत्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित नाला के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि एक करोड़ पैंतीस लाख बीस हजार नौ सौ रुपये मात्र है । नगर पंचायत, परबत्ता के बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर पंचायत, परबत्ता को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष : आप ऐसा न करें, ये आचरण अच्छा नहीं है, मार्शल, आइये । आप लोग इस टेबल को नीचे रखिए, इसको छोड़िए ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, ये भाजपा के लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, ये ताली पीट रहे हैं, ताली पीटने के लिए इनको टोल प्लाजा पर भेज दीजिए, कुछ आय भी होगा, ये विधान सभा में ताली न पीटें, टोल प्लाजा पर जाकर ताली बजायें, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके छोड़ दिये हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप बिहार विधान सभा में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से जीतकर आये हैं और आपकी कार्यवाही को आपके क्षेत्र की जनता देख रही है, आप प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं, ये लोकतंत्र पर खतरा है...

डॉक्टर संजीव कुमार : महोदय, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : और आप लोग इस टेबल को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं यह काफी आपत्तिजनक है, इस तरह का आचरण करना उचित नहीं है ।

माननीय सदस्य, डॉक्टर संजीव कुमार ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि परबत्ता में जो मार्केट है, वह हर साल पानी में डूब जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है, डेढ़ फीट पानी जम जाता है उसका निकास नहीं है । वहां से प्रशासनिक स्वीकृति के लिए 1 करोड़ 35 लाख का नाला का प्राक्कलन आ गया है जो पिछले छः महीने से यहां डिपार्टमेंट में लंबित है । मंत्री जी से मेरा यही आग्रह था कि इसको प्रशासनिक स्वीकृति ये दे दें । माननीय मंत्री जी का उत्तर भी हमें प्राप्त हुआ उसमें बोला गया

है कि 3 करोड़ 63 लाख है बोर्ड की मीटिंग में कर लेंगे, लेकिन उस 3 करोड़ 63 लाख में से मात्र 20-30 परसेंट ही नाला के लिए प्रावधान है तो इस तरह से वह 60-70 लाख रुपये के आसपास होगा और उससे वह नाला नहीं बनेगा । इसके लिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि 1 करोड़ 35 लाख रुपये यहां से नाला के लिए आवंटित कर देते, मुख्य बाजार का नाला है नगर पंचायत के अंतर्गत, इसलिए मैंने यह प्रश्न किया है, माननीय मंत्री महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं उसको दिखवा लेता हूं ।

डॉक्टर संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस बार मेरा आग्रह है कि इस बार बारिश में उसे नहीं डूबने दिया जाय और उसको करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वे इसको दिखवा लेंगे, इसलिए अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

<u>तारांकित प्रश्न सं0-368(श्री युसुफ सलाहउद्दीन, क्षेत्र सं0-76, सिमरी बख्तियारपुर)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री युसुफ सलाहउद्दीन, नहीं हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-369(श्रीमती नीतु कुमारी, क्षेत्र सं0-236, हिसुआ)</u>

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ विधान सभा क्षेत्र के हिसुआ (500 मि0टन), नरहट (500 मि0टन) एवं अकबरपुर (1000 मि0टन) प्रखंड में टी0पी0डी0एस0 एस0एफ0सी0 का गोदाम पूर्व से संचालित है ।

उल्लेखनीय है कि एस0एफ0सी0 गोदामों में धान की अधिप्राप्ति नहीं होती है । सी0एम0आर0 संग्रहण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर नये गोदामों के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि भूमि उपलब्ध है, नया गोदाम वहां पर बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ठीक है । आपने सूचना दी, मंत्री जी ने उसको ग्रहण कर लिया है, ये उसको दिखलवा देंगी और उस पर समुचित कार्रवाई करेंगी ।

श्रीमती नीतु कुमारी : मंत्री जी, धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0-370(डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: (1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, दिघवारा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित सड़क पर बरसात के दिनों में यत्र-तत्र जल-जमाव हो जाता है । इसके त्वरित निदान हेतु सक्शन मशीन एवं पम्प सेट द्वारा जल की निकासी की जाती है तथा टूटे हुए जगहों पर राबिश गिरा कर भराव किया जाता है।

(3) वर्णित सड़क एवं नाला के निर्माण हेतु ई-टेंडर के माध्यम से एन0आई0टी0 सं0-02/22-23 प्रकाशन कराया गया है, शीघ्र ही निविदा निष्पादित कर उक्त सड़क पर नाला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब में यह जानना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि उनको जो प्रतिवेदित किया गया है, अभी भी वहां पर जल-जमाव है माननीय मंत्री जी । आप आज भी जांच करवा लीजिए और आपने उसको बनवाने की बात कही है तो मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इसे इसी वित्तीय वर्ष में बनवा दिया जाय ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : देखिए, लोकतंत्र के इस मंदिर में माननीय नेता प्रतिपक्ष की आवाज को सरकार नहीं दबा रही है, बल्कि विरोधी दल के द्वारा इस तरह का जो कार्य हो रहा है उससे आप अपने ही काम को बाधित कर रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बताया गया है कि यत्र-तत्र जल-जमाव का सक्शन मशीन एवं पम्प सेट के द्वारा जल की निकासी की जाती है । यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में है कि वहां पर जल-जमाव है तो उसको दिखवा लिया जायेगा और उसके बाद जल्द-से-जल्द जल की निकासी की व्यवस्था जायेगी । जहां तक सड़क के निर्माण का मामला है तो बताया गया है कि ई-टेंडर हो चुका है और जल्द ही अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही उस कार्य में हाथ लगाने का प्रयास किया जायेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको कब तक करवा देंगे ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : एक महीना के अंदर जल निकासी की व्यवस्था और बाकी कार्य अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम चरण में करवा दिया जायेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।)

तारांकित प्रश्न सं0-371(श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-9, सिकटा)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित) : (1) अस्वीकारात्मक ।

समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार हेतु 2021 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश का अनुपालन करते हुए पिपरासी अंचल अन्तर्गत ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि निराकरण जैसे खाता, खेसरा, रकबा, नाम आदि का सुधार हेतु रिकॉर्ड ऑफ राइट (आर0ओ0आर0) के तहत 5284 जमाबंदियों में सुधार किया गया है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

क) अंचल पिपरासी में ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल में प्राप्त कुल 1572 आवेदन पत्रों में से 1504 आवेदन पत्रों का ससमय निष्पादन किया जा चुका है । मात्र 68 आवेदन लंबित है ।

ख) अंचल पिपरासी में ऑनलाइन भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (एल0पी0सी0) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कुल 72 भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्रों में से सभी 72 आवेदन पत्रों का ससमय निष्पादन किया जा चुका है । लंबित मामला शून्य है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ऑनलाइन जवाब आया हुआ है और जवाब में जो बातें दी गई हैं, यह पिपरासी अंचल का मामला है वहां पर हजारों ऐसे जमाबंदी हैं, जिनके नाम में जमाबंदी केवल नम्बर है लेकिन खाता, खसरा या रकबा नहीं है । फिर पिता के नाम में जो भूमिधारी है उसके नाम में गड़बड़ी की गई है । इसमें यह कहा गया है कि इसमें पिछले दिनों सुधार किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछिए, आपको पूरक प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम पूरक प्रश्न ही पूछ रहे हैं । महोदय, हमारे पास ऐसे हजारों लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनका कहीं भी जो जमाबंदी है उसका ट्रेस वहां पर नहीं मिल रहा है और यह सीधे तौर पर कम्प्यूटराइज दिखा रहा है कि वहां पर कोई जमाबंदी का ट्रेस नहीं मिल रहा है, कोई नहीं पाया जा रहा है ।

जबकि वहां पर अंचलाधिकारी के द्वारा यह जवाब दिया गया है कि हमने तमाम चीजों को कर दिया है और यहां पर कोई जमाबंदी सुधार के लिए नहीं है, लेकिन महोदय, हमारे पास ये तमाम सबूत हैं और इस ढंग से हजारों लोगों का है । दूसरी बात जो हमारा प्रश्न था कि उसमें परिमार्जन के लिए जो आवेदन दिया गया है उसमें भी कहा गया है कि परिमार्जन का कार्य पूरा हो गया है और एक भी काम बाकी नहीं है । लेकिन महोदय, हमारे पास परिमार्जन से भी संबंधित कागजात हैं उसमें यह सीधे तौर पर जो बातें सामने आई हैं कि उसमें लिखा गया है कि परिमार्जन हो चुका है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न में मुख्य चीजों को ही पूछा जाता है, इसे भाषण का रूप नहीं दिया जाता है ।

टर्न-4/यानपति/02.03.2023

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: महोदय, भाषण का रूप नहीं दे रहे हैं लेकिन जो बातें हैं कि वह सीधे तौर पर वहां जो जवाब दिया गया है कि वहां जो भूधारी हैं उनका परिमार्जन का कोई टास्क उनके जिम्मे नहीं है लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, हमारे पास यह सब पेपर हैं.....

अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य आप से कहना चाहता हूं कि उन तमाम कागजात को माननीय मंत्री जी के सामने दे दीजिए, माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: जी हमारी बात वह दिखवा लेंगे लेकिन वहां जो है कैंप लगवा कर के और जितना यह बाकी है हजारों लोगों का मामला उसको किया जाय वह परिमार्जन का काम और उनके जमाबंदी में खाता-खेसरा.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य.....

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: यह हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वह ऐसा कराने का विचार रखते हैं या नहीं ।

अध्यक्ष: आसन ने अपने स्तर से जो सरकार ने जवाब दिया उसी के संदर्भ में और जो कागजात आपके पास है, आसन ने यह कहा कि उसको आप माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, वह दिखवा लेंगे इसलिए मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न है और जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी, आप इनको अपने कागज को दे दीजिए अब मैं, माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-372 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0 93 कुढ़नी)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता: महोदय, मेरा तीन पूरक नहीं हुआ ।

अध्यक्षः आपका तीन पूरक नहीं हुआ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ताः कैंप लगेगा या नहीं लगेगा, कैंप वहां लगाकर इसका सुधार होगा या नहीं और दूसरा जो काम फिनिश दिखा रहे हैं अंचलाधिकारी वहां वह इसलिए रोके हुए हैं उसका रिमार्क्स कहीं दर्ज नहीं है कि उनको पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए और ऐसे हजारों मामले को लटका कर रखे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे ।

अध्यक्षः इन सारी चीजों को मंत्री जी अपने स्तर से दिखवा लेंगे और जो समुचित होगा वह करेंगे । माननीय सदस्य श्री रामप्रवेश राय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-373 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0 100 बरौली)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या-374 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0 194 आरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्या श्रीमती वीणा सिंह । आपको प्रश्न का जवाब प्राप्त है आप पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-375 (श्रीमती वीणा सिंह, क्षेत्र सं0 129 महनार)

श्रीमती वीणा सिंहः यदि हां तो क्या सरकार उक्त तालाब का सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अध्यक्षः समय चाहिए ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः दिखवा लेते हैं । इसका जवाब लगता है कहीं आगे-पीछे रखा गया है ।

अध्यक्षः जो जवाब आपके पास आ गया है उसको लेकर के माननीय सदस्या को आप दिखवा कर के भिजवा दीजिएगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्रीः मैं दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार मंटू ।

तारांकित प्रश्न संख्या-376 (श्री कृष्ण कुमार मंटू, क्षेत्र सं0 120 अमनौर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

तारांकित प्रश्न संख्या-377 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0 152 बिहपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-378 (श्री नारायण प्रसाद, क्षेत्र सं0 6 नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजू अग्रवाल ।

तारांकित प्रश्न संख्या-379 (श्रीमती मंजू अग्रवाल, क्षेत्र सं0 226 शेरघाटी)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्रीः अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, डोभी नये सरकारी भवन में क्रियाशील है जिसका निर्माण वर्ष 2011-12 में किया गया है । वर्तमान में डॉ0 शिवम श्री हर्ष, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, डोभी, गया में पदस्थापित हैं जिनके द्वारा उक्त पशु चिकित्सालय में नियमित रूप से चिकित्सा कार्य किया जा रहा है ।

जनवरी 2023 में पशु चिकित्सक द्वारा चिकित्सा- 320, बधियाकरण- 09 एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य- 74 किया गया है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्रीः महोदय, उत्तर तो उनको दे दिया गया है अगर कुछ पूरक पूछना चाहते हैं तो वह पूछें ।

अध्यक्षः वही तो मैं कहना चाहता हूं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें । माननीय सदस्या, आप पूरक पूछना चाहती हैं तो पूछें ।

श्रीमती मंजू अग्रवालः जी महोदय, हमारा पूरक यही है कि चिकित्सालय तो है लेकिन यहां पर चिकित्सक नगण्य हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और यह हमारे कजियार डोभी का ही मामला नहीं है, हर जगह बिहार में देखा जाय तो इसमें चिकित्सकों की संख्या नगण्य है और पशुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्रीः महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय डोभी नए सरकारी भवन में चल रहा है जहां पर डॉ0 शिवम श्री हर्ष प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय डोभी गया में पदस्थापित हैं और 2023 में पशु चिकित्सक द्वारा चिकित्सा 320 बधियाकरण 09 एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्य 74 की गई है तो महोदय डॉक्टर वहां पर ऑलरेडी हैं और मैंने उनका नाम भी बता दिया है कि वहां पर डॉक्टर उपस्थित हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है कि वहां पर व्यवस्था है इसलिए आप स्वयं देख लीजिएगा अगर कहीं व्यवस्था में आपको लगे कहीं कुछ कमी है तो माननीय मंत्री जी काफी ऊर्जावान हैं आप उनसे भेंट कर के अपनी

समस्या के निदान अगर हो, है तो नहीं अगर हो तो करवा लीजिएगा, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है, मैं पूरे बिहार का नहीं किया हूं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन प्रखंड है और तीनों प्रखंडों में पशु चिकित्सक नहीं रहते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: महोदय, अगर माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है वह हमारे विभाग को लिखित रूप से मुहैया करा देंगे तो हम जांच करेंगे । अगर अधिकारी वहां पर उनका पदस्थापन है नहीं जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी । वह लिखकर के बता दें कि हां ये डॉक्टर वहां पर नहीं आते हैं, कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लिखकर के दे दीजिएगा ।

श्री शकील अहमद खाँ: महोदय, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि अधिकारी वहां मौजूद रहेगा इसकी आपके पास मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है कि जो इन्होंने बात कही है वह लगभग सब जगह बराबर है, मॉनिटरिंग की व्यवस्था आजकल साइंटिफिक है, वह अगर करवा लेंगे तो उससे बेहतर परिणाम आपको निकल सकते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: महोदय, चूंकि कोई विभाग चलता है तो बिना व्यवस्था और बिना नियमावली के तो नहीं चलता है तो कोई ऐसा विभाग तो नहीं है जहां पर नियमावली नहीं है । अगर पर्सनली आपको कुछ कमियां दिखती हैं तो आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं, हमारा विभाग जो है उस पर अमल करेगा ।

श्री शकील अहमद खाँ: मैं आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता हूं यह राय है और डॉक्टर्स नहीं रहते हैं उस जगह पर, टाइमिंग क्या होगी उसकी आज के दिन में, स्कूलों से लेकर हर जगह एक मॉनिटरिंग बनाई गई है तो उसका साइंटिफिक तरीका है इनके पास आ जाएगा रोजाना, इसमें क्या दिक्कत है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य खान साहब, आपने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, संदर्भित मामले एक ही तरह के हैं और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप लिखित दे दीजिए या हम अपने स्तर से दिखवा लेंगे । इसलिए अब माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी ।

श्री राम रतन सिंह: अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-380 (श्री राम रतन सिंह, क्षेत्र सं0 143 तेघड़ा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, बरौनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विगत वर्ष छठ पर्व के अवसर पर दुलरुआ धाम तालाब की

साफ-सफाई विशेष रूप से कराई गई थी । वर्तमान में भी प्रतिदिन दुलरूआ धाम तालाब की साफ-सफाई कराई जाती है ।

नगर परिषद्, बरौनी की सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.02. 2023 के प्रस्ताव सं0- 03 द्वारा नवगठित नगर परिषद् बरौनी में अवस्थित दुलरुआ धाम तालाब बाउन्ड्री वाल, सीढ़ी, पार्क का निर्माण आदि कराने की स्वीकृति दी गयी है ।

कनीय अभियंता नगर परिषद् बरौनी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर परिषद्, बरौनी को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार बाउन्ड्री वाल, सीढ़ी, पार्क एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य नगर परिषद् बरौनी द्वारा किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, उत्तर दिया गया है, क्या उसे पढ़कर सुना दूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राम रतन बाबू, आपको उत्तर भेज दिया गया है आप पूरक पूछिए ।

श्री राम रतन सिंह: वर्षों से सरकारी तालाब है, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन में यह फैला हुआ है और हम समझते हैं कि वहां ढेर सारे पर्यटक आते रहते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लगातार खेल-कूद का कार्यक्रम होता है । इधर तालाब की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई है लोग उसको दखल कर रहे हैं अगल-बगल के लोग । इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका जीर्णोद्धार सरकार करना चाहती है या नहीं यह सीधा जवाब हमको चाहिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न को उठाया था उसी को उन्होंने एलोवरेट किया । अभी व्यवस्था नगर विकास विभाग के अंदर यह है कि नगर निकायों को खुद वहां की व्यवस्था के लिए, वहां के कंस्ट्रक्शन के लिए सारी योजनाओं को बनाना होता है तो जीर्णोद्धार की योजना है नगर परिषद् बरौनी को बनानी होगी सशक्त समिति की बैठक 03.02.2023 के प्रस्ताव संख्या-3 द्वारा नवगठित नगर परिषद् बरौनी में अवस्थित दुलरूआ धाम तालाब बाउंड्री वाल सीढ़ी, पार्क आदि का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है तो कनीय अभियंता नगर परिषद् बरौनी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर परिषद् बरौनी को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार बाउंड्री वाल, सीढ़ी, पार्क एवं सौंदर्यीकरण का काम नगर परिषद् बरौनी द्वारा ही किया जाना है तो पैसा सरकार नगर निकाय को दे देती है, योजना नगर निकाय को बनाना है और उसके आगे काम आगे बढ़ चुका है ।

टर्न–5/अंजली/02.03.2023

श्री राम रतन सिंह : यहां से कोई लिखित आदेश अगर चला जाता है तो इसमें बनवाने में आसानी होगी । यह हमारा कहना है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : लिखित आदेश पैसा भेजने के लिए हो सकता है लेकिन जो योजना है वह उधर से ही आनी है और उधर से बनाकर उसको कार्यान्वित करना है । इसलिए फिर भी मैं दिखवा लेता हूं कि क्या प्रगति है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सशक्त कमेटी है, बोर्ड है, आपने ठीक ही कहा कि उससे पारित होनी चाहिए और राशि देने की बात है, जब योजना बनकर तैयार होकर के आपसे राशि मांगी जाएगी तो आप उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री ऋषि कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–381, श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या–220 ओबरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्या, श्रीमती नीतु कुमारी ।

तारांकित प्रश्न संख्या–382, श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या–236 हिसुआ)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि (1) नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड अंतर्गत खरसारी पैक्स द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में 20 (बीस) किसानों से 201.5 (दो सौ एक दशमलव पांच) मे0 टन धान की खरीद की गई तथा संबंधित किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कर दिया गया । खरसारी पैक्स द्वारा रबी विपणन मौसम 2019–20 में गेहूं अधिप्राप्ति कार्य नहीं किया गया है ।

(2) खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में खरसारी पैक्स द्वारा 134 (एक सौ चौतीस) किसानों से 1293.4 (एक हजार दो सौ तिरानवे दशमलव चार) मे0 टन धान की खरीद की गई तथा संबंधित किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कर दिया गया । खरसारी पैक्स द्वारा रबी विपणन मौसम 2021–22 में 15 (पन्द्रह) किसानों से 81(इक्यासी) मे0टन0 गेहूं की खरीद की गई तथा संबंधित किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कर दिया गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपको जवाब उपलब्ध करा दिया गया है आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती नीतु कुमारी : महोदय, मैं यह यही कहना चाहूंगी कि इस पंचायत में 20 किसान का मेरे पास नाम है जिसको अभी तक पैसा भुगतान नहीं हुआ है । आपका डिपार्टमेंट

पैसा भुगतान कर दिया है लेकिन सही किसान को नहीं मिला है । कहीं-कहीं ऐसा मामला हुआ है कि पिता जो है वह धान दिया है और बेटे को पेमेंट चली गई है, इसकी जांच करवाकर और जो सही किसान हैं उनको राशि भुगतान करवा दी जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसकी हम जांच करवा देंगे क्योंकि हमलोग पैसा दे चुके हैं ।

अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । अब आप बैठ जाइए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-383, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान । आप पूरक पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : जवाब नहीं मिला है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : माननीय सदस्य को उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने नहीं देखा है, इसलिए मैं जवाब पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं एवं 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से प्राप्त अनुशंसा सूची के आधार पर राज्य के विभिन्न अंचल कार्यालयों में राजस्व अधिकारी का पदस्थापन किया गया है । तथापि, रिक्ति के अनुरूप कतिपय अंचल कार्यालयों में राजस्व अधिकारी का पदस्थापन नहीं किया जा सका है ।

एतदर्थ आयोग की 67वीं एवं 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर राजस्व अधिकारी समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग में प्रेषित है । आयोग से अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त होने पर रिक्त अंचल कार्यालयों में राजस्व अधिकारी का पदस्थापन किया जायेगा ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जिस जटिल प्रक्रिया बात की है उससे ऐसा लगता है कि साल भर और लग जाएंगे । अमौर प्रखंड 25 पंचायतों पर आधारित है और घनी नदियों के कारण हर साल जमीन का कटाव होता है, बसावट के मसले होते हैं और भूमि का काफी विवाद है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे बहाली के प्रति आशा में नहीं बल्कि उन छोटे प्रखंडों में जहां पर इन्होंने राजस्व पदाधिकारी दिया है, कहीं से हमारे यहां प्रतिनियुक्त कर दें ताकि वहां की समस्याओं का हल हो और मंत्री जी काफी गंभीर हैं तो मैं आशा करता हूं जरा सा जल्दी कर दें ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : मैं इसको दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुर्यकांत पासवान जी आप इसी संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं?

श्री सुर्यकांत पासवान : जी महोदय ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के डंडारी प्रखंड में, सी0ओ0 साहब हम समझते हैं रिटायर हो चुके हैं, अभी वह पद खाली है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां सी0ओ0 की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न जो है, पूर्व के जो प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने स्पेसिफिक जगह का नाम दिया है और सरकार ने उसी के संबंध में सूचनाएं मंगाई होंगी और सूचना के आधार पर माननीय सदस्य को माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया । आप जिस विषय को उठा रहे हैं, उससे जोड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सत्र लंबा है, आप अगर उस प्रश्न को पुनः अपने उस स्पेसिफिक अंचल के लिए उठायेंगे, सरकार उसको देखेगी और सरकार आपकी समस्या के निदान के संबंध में कार्रवाई करेगी । इससे संदर्भित आपका मामला माननीय सदस्य, पासवान जी नहीं बनता है ।

माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार रौशन ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-384, श्री मुकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-126 महुआ)</u>

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित उत्तर) : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

समाहर्ता नालंदा के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, नालंदा के पंत्राक-4807, दिनांक-22.10.2022 के द्वारा वर्णित तथ्यों का जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, एकंगरसराय को निदेशित किया गया था ।

उक्त के आलोक में कहना है कि सर्वे खाता सं0-276, ई सर्वे खेसरा सं0-1524, रकवा-64डी0, सर्वे खाता संख्या-311, सर्वे खेसरा संख्या-1695, रकवा-64डी0 गैरमजरूआ आम किस्म भूमि पईन सर्वे खतियान में दर्ज है । सर्वे खेसरा संख्या-1648, रकवा-49डी0 की जमीन सर्वे खतियान से नया चक खेसरा संख्या-1410, रकवा-49डी0 का खतियान बना । उक्त रकवा 49डी0 में से 15/3/4 डी0 सुरेन्द्र प्रसाद के नाम से क्रय की गई भूमि है । चक खतियान से नया चक खेसरा 1410 बना जिसमें खेसरा 1524 पईन की भूमि को भी नक्शा में शामिल कर दिया जिसे भूमि विवाद वाद संख्या-59/2010-11 में चकबंदी नक्शा में संशोधन करते हुए दिनांक-13.05.2011 को आदेश पारित किया गया । सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा भू-विवाद अपील वाद संख्या-74/2011 आयुक्त महोदय, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष दायर की गई जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता हिलसा के आदेश दिनांक-13.05.2011 को यथावत रखा गया है । ऐसी स्थिति में दिनांक-01.02.

2013 को उक्त वर्णित भूमि पर पक्का पीलर स्थापित किया जा चुका है, जो वर्तमान समय में भी स्थल पर मौजूद है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, हमने जो सवाल किया था वह रकवा लगभग 6.25 डिसमिल का मामला था और जो पदाधिकारी हैं वे इसमें गलत रिपोर्ट दिए हैं । महोदय, ये लगभग 16 डिसमिल जमीन के बारे में इन्होंने चर्चा की है तो जो दोषी पदाधिकारी हैं, जो रिपोर्ट गड़बड़ किए हैं, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहेंगी जिन्होंने सरकार को गलत रिपोर्ट दी है।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, प्रतिवेदन में जो भी वर्णित है उस बात को यहां पर रखा गया है और सचमुच यदि गलत है तो उसकी हम जांच करवाते हैं देखेंगे क्या है ? माननीय सदस्य के द्वारा बताया कि डिफरेंस है तो हम पहले उसकी सच्चाई की जांच करवा लेते हैं फिर उस पर कोई बात होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार गुप्ता ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–385, श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या–208 सासाराम)</u>

श्री अलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, नगर आयुक्त, नगर निगम, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर निगम, सासाराम क्षेत्रान्तर्गत पूर्व के सभी 40 वॉर्डों में EESL द्वारा एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य कराया गया है । EESL द्वारा इल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईटों का रख–रखाव किया जाता है ।

नगर निगम सासाराम क्षेत्रान्तर्गत नवगठित वॉर्डों में स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु EESL (Energy Efficiency Services Limited) से पत्राचार किया जा रहा है ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, ये नगर आयुक्त जो जवाब दिये हैं ये बिल्कुल गलत दिए हैं । 40 वॉर्ड में कुछ ही ऐसे वॉर्ड हैं जहां पर स्ट्रीट लाईट लगा हुआ है और बाकी वॉर्ड का जो लगा हुआ है वह भी जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है, कोई रख–रखाव नहीं होता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नगर आयुक्त जवाव नहीं दिये हैं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जो होंगे वे जवाब दिये होंगे ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : नहीं महोदय, अब नगर निगम हो गया है ।

अध्यक्ष : निगम हो गया है ?

श्री राजेश कुमार गुप्ता : जी । और कुछ ही वॉर्ड में लाईट लगा हुआ है और उसका भी कहीं रख–रखाव नहीं है तो कोई योजना है नया स्ट्रीट लाईट लगाने का ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, इसको दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : जी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री नारायण प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-386, श्री नारायण प्रसाद (क्षेत्र संख्या-6 नौतन)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-387, श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-388, श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-389, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकट)

माननीय सदस्य, श्री अरूण सिंह । माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

श्री ललित कुमार यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया है जो विभागीय पत्रांक-297, दिनांक-18.02.2023 द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-390, श्री विजय कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार मंडल । माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है । महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पंचायत, दिनारा को षष्टम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत राशि एक करोड़ पचास लाख बानवे हजार नौ सौ सोलह रुपये मात्र प्राप्त हुआ है ।

नगर पंचायत, दिनारा के बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर पंचायत, दिनारा को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन किया जा जाएगा ।

2. उपरोक्त खंड में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

श्री विजय कुमार मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक है । महोदय, एक करोड़ पचास लाख में मात्र बीस परसेंट ही हमलोग इसमें खर्च कर सकते हैं तो इसमें मात्र तीस लाख रुपया होगा तो तीस लाख रुपया में क्या होगा ? माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इसमें राशि बढ़ाने की कृपा करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, षष्टम वित्त आयोग के तहत उतनी राशि दी गई है । पंचदश आयोग के तहत भी राशि दी जाती है तो निर्णय और जो योजना है वह नगर निकायों को ही करना है, जिसमें माननीय सदस्य भी उसके एक सदस्य हैं । माननीय विधान सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य भी नगर निकायों के सदस्य होते हैं । इसलिए जो राशि है उसी के अंदर प्राथमिकता के आधार पर करना है तो

प्राथमिकता का जो गाइडलाइंस है वह नगर निकाय को दिया हुआ है । इसलिए उसके अनुरूप नगर निकायों को निर्धारित करना है । राशि घटने-बढ़ने की जो बात है वह सरकार से कम्यूनिकेट करेगी तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद और माननीय विधायक इसमें 17 परसेंट ही खर्च कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो राशि उपलब्ध है और उस उपलब्ध राशि से आपकी योजनाओं का कार्यान्वयन संपूर्ण रूप से नहीं होगा जैसा कि आप बोल रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां से कोई राशि के कठिनाई के संबंध में आएगा तो सरकार उसको देखेगी, यही बात माननीय मंत्री जी आपको जानकारी देने का काम किए हैं इसलिए आपको अब स्थान ग्रहण करना चाहिए ।

श्री विजय कुमार मंडल : महोदय, एक बात कहकर के हम बैठ जाते हैं कि माननीय मंत्री जी कुछ राशि बढ़ा दें जिससे कि वहां का काम हो सके । काम सब रुका हुआ है, बड़ा जगह है । एक बार पुनः हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उसमें राशि बढ़ा दें ।

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/02-03-2023

तारांकित प्रश्न संख्या- 391(श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव,
क्षेत्र सं0- 216 जहानाबाद)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः महोदय, यह प्रश्न स्थानांतरित किया गया है जल संसाधन विभाग में ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः अध्यक्ष महोदय ,यह नगर परिषद का इश्यू है महोदय और चूंकि हमने नगर विकास एवं आवास विभाग से ही सवाल किया है, जल संसाधन का कोई उसमें जगह नहीं बनता है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जाफरगंज के पास गोरक्षी एवं संगम घाट को जोड़ने हेतु पूर्व में फुट ब्रिज निर्मित है, फुट ब्रिज का निर्माण माननीय सांसद विकास निधि से हुआ है जो जल संसाधन विभाग की भूमि पर निर्मित है । अतः दिनांक 02-03-2023 को जो सदन में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का प्रश्नोत्तर

विधान-सभा सचिवालय को भेजने की कृपा की जाय । ऐसा प्रतिवेदन दिया गया है संयुक्त निदेशक के द्वारा ।

अध्यक्ष: इसका मतलब कि स्थानांतरित है ?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष: जल संसाधन विभाग को?

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: जी ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, मतलब एक हम आग्रह करेंगे सरकार के माननीय मंत्री महोदय लोगों से कि जो पदाधिकारी जिला से अनाप शनाप प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं, इस पर कम से कम नियंत्रण रखा जाय । वहां एक बड़ी आबादी वाला जाफरगंज है जो अल्पसंख्यकों का है और उसके बगल में पुल है महोदय लेकिन वह एक छिलका टाईप का बना हुआ है नदी में और बरसात के दिनों में वह पूरी तरह से बंद रहता है और वह फुट ब्रिज जो है वह काफी दूर पर है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपने दिक्कत को, कठिनाई को जनता की जो समस्या है उसको आपने प्रश्न के माध्यम से सदन में लाया और माननीय मंत्री ने कहा कि स्थानांतरित है जल संसाधन विभाग को, सत्र लंबा है जल संसाधन विभाग का तो इंतजार कीजिये कि वह जो जवाब देते हैं क्या जवाब देते हैं इसलिए आप स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 392(श्री राणा रणधीर,क्षेत्र सं0-18,मधुबन)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 393(श्री कृष्ण कुमार मंटू,क्षेत्र सं0-120 अमनौर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 394(डॉ0 रामानुज प्रसाद,क्षेत्र सं0- 122 सोनपुर)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री: महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना नगर निगम नूतन राजधानी अंचल क्षेत्रान्तर्गत वार्ड संख्या-19 स्थित गौरियामठ मंदिर से यारपुर बन्द गुमटी तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को नियमित अंतराल पर अभियान चलाकर हटाया जाता है एवं जुर्माने के तौर पर राशि की वसूली भी की जाती है, ताकि आम जनता एवं स्कूल के छात्र-छात्राओं को आवागमन में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के प्रश्न से चूंकि कार्रवाई जिन्होंने किया है, सरकार ने किया है उस कार्रवाई के संबंध में माननीय मंत्री ने आपको बतलाया ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः महोदय, कार्यवाही के संबंध में जो माननीय मंत्री जी के द्वारा या विभाग द्वारा जो प्रतिवेदित किया गया है अध्यक्ष महोदय, उसको मैंने देखा है । मैं पूरक में यह जानना चाहता हूॅ कि बगल में विद्यालय है, उच्च विद्यालय है, बच्चों को आने जाने में जो कठिनाई होती है । हमलोग भी बगल का इलाका है आते जाते हैं स्थायी निदान, स्थायी जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए माननीय मंत्री जी विभाग को निर्देशित करेंगे ? जवाब में कहा गया है कि समय समय पर किये जाते हैं और वसूली भी की जाती है तो मैं चाहूंगा कि वसूली नहीं की जाय लेकिन वहां स्थायी निदान करा दिया जाये ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः अभी तक सरकार के पास कोई स्थायी निदान हेतु योजना लंबित नहीं है लेकिन एक अंतराल पर जब इसको खाली कराया जाता है तो जुर्माना लेकर, उसका कोई रेंट नहीं लिया जाता है,जुर्माने के तौर पर उससे पैसा लिया जाता है और जुर्माना इसलिए लिया जाता है कि अगली बार वे ऐसा न करें लेकिन बार-बार रिपिट हो रहा है इसलिए रिपिटेडली यही किया जा सकता है कि अंतराल को घटाया जा सकता है और 6 महीना पर जो खाली कराया जाता था तो उसको तीन महीना पर खाली कराया जायेगा ताकि वो वहां पर जमे नहीं,स्थायी रूप से नहीं रहें ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अस्थायी तौर पर कराते रहते हैं लेकिन मैं कहता हूॅ कि स्थायी निदान के तौर पर कुछ रास्ते जो स्कूल होकर जाता है उसको परमानेंटली वहां से इंक्रोचमेंट फ्री करवा दिया जाय कि बच्चों को कम से कम तकलीफ नहीं हो आने-जाने में ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः इसको दिखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-395(श्री देवेश कांत सिंह,क्षेत्र सं0-111,गोरैयाकोठी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 396(डॉ0 निक्की हेम्ब्रम,क्षेत्र सं0-162,कटोरिया,अ0ज0जा0)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 397(श्री बीरेन्द्र सिंह,क्षेत्र सं0-234,वजीरगंज)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 398(श्री अचमित ऋषिदेव,क्षेत्र सं0-47 रानीगंज,अ0जा0)

अध्यक्षः माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पंचायत, रानीगंज को षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि तीन करोड़ नौ लाख साठ हजार दो सौ छियानबे रूपये मात्र प्राप्त हुआ है। इस आवंटित राशि से नाला एवं सड़क निर्माण भी कराया जा सकता है ।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रानीगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, रानीगंज क्षेत्रांतर्गत वार्ड संख्या-17 सहित अन्य सभी वार्डों में जल निकासी पंप सेट एवं मानव बल के माध्यम से की जा रही है ।

नगर पंचायत, रानीगंज में कनीय अभियंता के पदस्थापन हेतु जिला पदाधिकारी, अररिया से अनुरोध किया गया है । कनीय अभियंता के पदस्थापन होते ही वर्णित नाला के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा। नगर पंचायत, रानीगंज के बोर्ड के निर्णय के आलोक में नगर पंचायत, रानीगंज को उपलब्ध राशि के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार इस योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य,माननीय मंत्री द्वारा आपके प्रश्न का सक्षम जवाब दिया गया है ।

श्री अचमित ऋषिदेवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को उत्तर अच्छा दिया है इसलिए धन्यवाद देते हैं। उत्तर साकारात्मक मिला है और पूर्ण विश्वास है कि रानीगंज के नाला का काम जरूर होगा । धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 399(श्री शंभू नाथ यादव,क्षेत्र संख्या- 199 ब्रहमपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्रीः समाहर्त्ता, बक्सर के प्रतिवेदनानुसार यह बात सही है कि श्री संत कुमार सिंह, सा0-छोटका सिंहनपुरा, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर के द्वारा पारस नाथ सिंह की पत्नी देवमुनी देवी, सा0-रमधनपुर के नाम संधारित दाखिल-खारिज वाद संख्या-109/2017-18 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, डुमरॉव के न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-156/2017-18 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 12.03.2019 को पारित आदेश में उक्त दाखिल-खारिज को विखण्डित किये जाने के उपरांत अंचल कार्यालय सिमरी के विविध वाद सं0-02/2020-21 संधारित कर दाखिल-खारिज वाद संख्या-109/2017-18 से सृजित नये जमाबंदी को बंद कर पुराने जमाबंदी, जो श्री संत कुमार सिंह वगैरह के नाम से था, को कायम किया गया है तथा श्री संत कुमार सिंह, सा0-छोटका सिंहनपुरा से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल

कार्यालय सिमरी द्वारा मापी वाद संख्या-50/2021-22 संधारित कर मौजा-मिश्रवलिया, थाना-138, खाता सं0-36, खेसरा सं0-57, रकबा-0.65 एकड़ एवं खेसरा सं0-62, रकबा-0.32 एकड़ भूमि की अंचल अमीन द्वारा मापी कर चिन्हित कर दिया गया है । तत्पश्चात संत कुमार सिंह द्वारा भूमि को अवैध दखल से मुक्त कराने हेतु शनिवारीय बैठक में प्राप्त आवेदन के आलोक में दोनों पक्षों को नोटिस कर सुनवाई की गयी । चूँकि भूमि रैयती खाते की है, फलतः सुनवाई के क्रम में आवेदक संत कुमार सिंह को बी0एल0डी0आर0 एक्ट 2009 के तहत सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, डुमरॉव के न्यायालय में आवेदन दाखिल करने का सुझाव दिया गया है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री शंभु नाथ यादवः अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैं धन्यवाद भी दे दिया । मैं आसन से जानना चाह रहा हूँ महोदय कि ये विपक्षी लोग इतना नंगा नाच करते हैं, आसन उन पर कड़ा ऐक्शन क्यों नहीं लेती है ?

अध्यक्षः अच्छा, अच्छा ठीक है स्थान ग्रहण कीजिये । वे अपने बिहार की जनता को कितना अच्छा प्रदर्शन और जनतंत्र में कितना उनका विश्वास है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं बिहार की जनता उनके सारे कारनामों को देख रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-400 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता,क्षेत्र सं0-20,चिरैया)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 401(श्री रित लाल राय,क्षेत्र सं0- 186,दानापुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 402(श्री विजय कुमार खेमका,क्षेत्र सं0- 62 पूर्णियां)

(अनुपस्थित)

टर्न-7/मधुप/02.03.2023

तारांकित प्रश्न संख्या-403 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र सं0 34, बाबूबरही)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, समाहर्त्ता, मधुबनी के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजौली के उत्तरी भाग में बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है । प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि चहारदिवारी नहीं रहने के कारण कुछ रकबा अतिक्रमित कर लिया गया है । जिसके लिए अतिक्रमण वाद संख्या 01/2023 संधारित कर दिनांक 01.03.2023 को नापी की तिथि निर्धारित की गयी थी ।

अतिक्रमण चिन्हित होने पर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिवत अतिक्रमण खाली करा दिया जायेगा। निरीक्षण के क्रम में ग्रामीण/स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मी द्वारा बताया गया कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तथा आवारा पशुओं के बसेरा से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अतिक्रमित स्थल को चिन्हित कर विधिवत अतिक्रमण मुक्त करा लिया जायेगा ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, कबतक अतिक्रमण मुक्त करा लिया जायेगा और उसमें बाउंड्री वॉल कबतक होगा ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, हमने बताया कि उसकी नापी का कार्य जल्द से जल्द करा लिया जा रहा है । नापी के बाद यह पता चलेगा कि अतिक्रमण है कि नहीं, जबतक अतिक्रमण पता नहीं चलेगा तबतक अतिक्रमण कैसे खाली कराया जाय ।

अध्यक्ष : तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-02 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री विजय कुमार खेमका, श्री जय प्रकाश यादव, श्री संजय सरावगी, श्री लखेन्द्र कुमार रौशन एवं श्री जनक सिंह । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 171(1) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत में पीपल डांगी मरीया वार्ड नं0-11 के समीप सखुआडांगी कानर में चेक डैम नहीं रहने के कारण हजारों एकड़ भूमि का फसल बर्बाद हो जाता है ।

अत: मैं उक्त स्थल पर चेक डैम बनवाने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, गया जिले के बेलागंज अंचल में महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान आंदोलन के प्रखर नेता पंडित यदुनंदन शर्मा की कार्यस्थली ऐतिहासिक नेयामतपुर आश्रम वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है । इसे राजकीय धरोहर घोषित करने और उनके नाम पर कृषि शोध संस्थान शुरू करने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-बार के ग्राम-हरना मोड़ से नहर तक रोड एवं नहर पर पुलिया का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री भरत बिंद : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामपुर में सोन स्तरीय बगही माइनर की सफाई एवं मरम्मती नहीं होने से क्रमश: रामपुर, पाली, भलुआ, निसिजा, कुड़ारी, तेनुआ, शिवपुर आदि गाँवों की सिंचाई के अभाव में दोनों फसल मारी जाती है ।

उक्त नहर की सफाई एवं मरम्मती की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 2023 के रात्रि में शिवाजी चौक, रामकृष्णा नगर, फुलवारीशरीफ में शॉट सर्किट से आग लगने से एक दर्जन दुकानें जलकर राख हो गयी । सभी दुकानदार कमजोर थे ।

अतः सरकार से आपदा के माध्यम से राहत की माँग करता हूँ ।

श्री राम रतन सिह : अध्यक्ष महोदय, तेघड़ा विधान सभा अन्तर्गत तेघड़ा प्रखंड के रातगांव पंचायत में भगवानपुर चक्की, आधारपुर एवं निपनिया पंचायत में गंगा नदी से भीषण कटाव हो रहा है । कटाव से लाखों की आबादी के जान-माल की सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरकों की कटौती के बीच बिहार में यूरिया की खपत को ध्यान में रखते हुए, आगामी खरीफ सीजन के लिए राज्य अपने स्त्रोतों से किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध करावे ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखण्ड के मंझली गाँव में विद्युत कृषि फीडर से किसानों के नलकूप को जोड़ने की माँग करता हूँ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत पालीगंज प्रखंड के नगवां गांव में नवनिर्मिल जेल का नामकरण अमर शहीद श्री हरदेव नारायण सिंह के नाम पर किया जाए ।

जेल से सटे तोरणी गांव निवासी हरदेव बाबू का निधन 1923 में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के आह्वान पर झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान नागपुर जेल में हुआ था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, घोसी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एन0एच0 110 के मननपुर मोड़ से गिरधरपुर तक जाने वाली सड़क काफी जर्जर है । सड़क मरम्मती की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण जिले के मैनाटांड़ प्रखंड में नेपाल से आने वाली जेहरम और ओरिया जैसी नदियॉं हैं जिसमें बालू खनन पर रोक लगाया गया है । जिससे बाढ़-कटाव की समस्या बढ़ गई है । यथाशीघ्र बालू खनन चालू कराने की मॉंग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(अनुपस्थित)

श्री अख्तरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं जो पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं किन्तु नियोजित शिक्षकों के वेतन और नियमित शिक्षकों के वेतन में बड़ी असमानता है ।

अत: मैं सरकार से नियोजित शिक्षकों को समान वेतन एवं पेंशन देने की मॉंग करता हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बन्द होने से गरीब छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है । अत: छात्रों की छात्रवृत्ति अविलम्ब बहाल कराने की मॉंग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(अनुपस्थित)

टर्न-8/आजाद/02.03.2023

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड बोखड़ा के ग्राम पतनुका से सिंघाचौड़ी सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है । यह सड़क सम्पूर्ण प्रखंडवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है । सड़क खराब होने के कारण आमजनों को कठिनाईयां होती है । जनहित में सरकार से सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित बिहार के सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहिन अथवा एकल शिक्षकीय अवस्था में चल रहा है, जिस कारण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है ।

मैं सरकार से ऐसे मदरसों को चिन्हित कर नई नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में टी0ई0टी0 पास D.el.ed/B.ed सत्र 2015-17 और 2016-18 (नियमित कोर्स) में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को महाविद्यालय से विरमण की तिथि से ग्रेड-पे का लाभ देने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 से वार्ड सचिव पद पर कार्यरत 114691 वार्ड सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है । इन वार्ड सचिवों को जनहित में पुनः काम पर रखने या किसी दूसरे विभाग में समायोजित करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केशरी ।

(अनुपस्थित)

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी0एस0एस0सी0 द्वारा 2014 में आयोजित प्रथम इन्टर स्तरीय परीक्षा के 8 साल बाद घोषित रिजल्ट में कुल 13120 पदों के विरूद्ध योग्यता के बावजूद 11329 पदों के लिए ही अभ्यर्थियों का चयन किया गया है । शेष 1778 काउंसिलिंग कराये अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार राज्य में महादलित के उत्थान हेतु 10 वर्ष पूर्व विकास मित्रों का नियोजन किया गया था । सरकारी कर्मी की तरह काम भी करते हैं । मगर सरकारी कर्मी नहीं होने से सारी सुविधाओं से वंचित हैं ।

कर्मचारी का दर्जा, यात्रा भत्ता 3000 इत्यादि देने की मांग करता हूँ ।

महादेय, ये लोग बहुत ही मेहनत का काम करते हैं .....

अध्यक्ष : आपने शून्यकाल पढ़ दिया, इसपर विमर्श नहीं होंगे ।

श्री सत्यदेव राम : ये समाज के सबसे निचले पायदान के लोग हैं, सरकार को इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, यह मैं बार-बार मांग कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : सरकार जनता के प्रति काफी संवेदनशील है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोज मंजिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी0एस0एस0सी0 द्वारा 2019 में ही 1374 सहायक उर्दू अनुवादकों की बहाली निकाली गई थी, लिखित परीक्षा ली गई और

26 जुलाई से 8 अगस्त, 2022 तक काउंसिलिंग की गई थी लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया । अविलम्ब नियुक्ति पत्र देने की मांग करता हूँ ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के कुर्था थाना निवासी राम प्रवेश साव के दुकान माया आलू एवं फूट भंडार से अपराधियों ने 5,50,000/- रू0 हथियार के बल पर लूट लिया जिसका कुर्था थाना कांड सं0-55/23 है ।

अतः लूटी गई राशि की शीघ्र बरामदगी एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री विनय कुमार चौधरी : महोदय, दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड अन्तर्गत कमरकाला पंचायत के कमला नदी पर गमहरिया से हरसेर के बीच पुल का निर्माण किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

(अनुपस्थित)

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वित्तीय कम्पनी ने बिजली दर में 40 फिसदी और फिक्सड चार्ज में दो से ढ़ाई गुना वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को दिया है । लोकहित में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को रद्द करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह ।

(अनुपस्थित)

अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री रामबली सिंह यादव, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामबली सिंह यादव जी की ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री जी विधान परिषद् में हैं, उनका प्रश्न वगैरह वहां पर है । इसलिए कल इसका उत्तर होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न के उत्तर कल माननीय मंत्री जी देंगे ।

सर्वश्री राजेश कुमार, श्री महा नंद सिंह एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए लोक महत्व का जो विषय चयन किया गया है ध्यानाकर्षण सूचना, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, ''बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकगण बिहार के ग्राम पंचायतों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं । विगत वर्षों के कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तब प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था संधारण में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की अहम मदद ली गई थी । यदा-कदा पूजा-पाठ, पर्व त्योहारों के अवसरों पर भी इनकी सेवा ली जाती रही है । इनकी स्थिति भुखमरी के दरवाजे पर खड़े बेरोजगारों सी है, जबकि इन्हें समायोजन कर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आने वाले गाँवों में शराबबंदी, बाल-विवाह व अवैध बालू खनन की रोकथाम और गाँवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ की जा सकती है । साथ ही प्रदेश की पुलिस एवं जिला प्रशासन पर गाँवों की सुरक्षा के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है ।

अतः बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायतों में समायोजन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल संगठन कर्त्तव्य एवं व्यवहार नियमावली 2004 के नियम 3 के उप नियम-3 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत के ग्राम रक्षा दल एवं स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है । दल के सभी सदस्यों क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं दलपति की कार्य अवधि 5 वर्षों की होती है।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं एवं यह एक स्वयंसेवी संगठन है । इस नियमावली के कंडिका-8 में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को निर्धारित कर्त्तव्यों के अनुरूप ही इनसे कार्य लिया जाता रहा है । नियमावली 2004 के नियम-17 में प्रावधान किया गया है कि दल से संबंधित सभी व्यय का वहन ग्राम पंचायत के निधि से किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायत में समायोजन करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

टर्न-9/शंभु/02.03.23

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये पांच साल का कार्यावधि रहा है, लेकिन मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वर्ष 1981 ई0 से राज्य में ग्राम रक्षा दल सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 1989 से चौकीदारों और दफादारों का स्थायीकरण किया गया, किन्तु ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों का स्थायीकरण नहीं हुआ । उन्हें सिर्फ दैनिक वेतन भत्ता-आश्चर्यजनक है महोदय कि 2 रू0 से इनको कार्य में लगायी थी सरकार और 2 रू0 से बढ़ाकर 12 रू0 प्रतिदिन सरकार ने किया है, लेकिन जैसा मंत्री महोदय कहना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इसी के समतुल्य 2015 में जब पांच साल का कार्यकाल था तो 2015 में पटना जिला प्रशासन द्वारा जिलादेश पत्रांक-4863, दिनांक-15.11.2015 के द्वारा लोक आस्था के महापर्व में इनको दंडाधिकारी के साथ इनकी सेवा ली गयी । दूसरे औचित्य में कोरोना काल के समय वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा आधिकारिक तौर पर इनकी सेवा ली गयी है । अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर सरकार से यह मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि जब इनकी सेवाकाल पांच साल है तो पांच साल के बाद फिर ये 2015 में और उसके बाद कोरोना आयी 2000 तो ये फिर मुजफ्फरपुर में इनसे काम लिये जा रहे हैं तो पांच साल की अवधि क्यों नहीं एक्सटेंड करके समायोजन करते हैं । इसलिए मेरा एक पूरक होगा कि क्या सरकार ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को स्थायी समायोजन कराना चाहेगी?

मो0 जमा खान,मंत्री : मैं सदस्य महोदय से कहना चाहता हूँ इसे मैं देखवा लेता हूँ बैठकर बात कर लेंगे ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा ठीक कह रहे हैं उनका जो सरकार द्वारा प्रशिक्षण हुआ है, ये 2015 काल में प्रशिक्षण हुआ है । उसके बाद भी सरकार लगातार काम ले रही है तो मैं सीधे आग्रह करूँगा कि हमारी महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देती है, यदि इनके परिवार को मानदेय फिक्स हो जाय और इनसे टाइम टू टाइम आप काम ले ही रहे हैं तो इनका एक मानदेय फिक्स हो जाय । यदि मानदेय फिक्स हो जाता है और ये इतना काम कर रहे हैं, अभी घर में बैठे हैं, बच्चा और बीबी प्रताड़ित करती है कि न आप सरकार के अंग हैं और न- इसलिए मैं पुनः पूरक पूछता हूँ कि इनको क्या सरकार समायोजन कराना चाहती है या समायोजन करने में कोई कठिनाई है तो इनको मानदेय फिक्स कर दे ।

मो0 जमा खान,मंत्री : मैंने कहा है इसपर बैठकर हम बात कर लेते हैं, देखवा लेते हैं तो हमको थोड़ा समय दें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, देखवाने में और करने में अंतर होता है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसमें सारे गरीब के परिवार हैं, पिछली पंक्ति के लोग हैं और पिछली पंक्ति के लोगों को आप देखवा लेंगे, आप इतना उदार हैं । आप इसका मानदेय फिक्स कर दीजिए जो भी फिक्स करना है । हमारी सरकार की मंशा साफ है लोगों के प्रति, गरीब के प्रति इसलिए इसका मानदेय फिक्स कराइये सर ।

मो0 जमा खान,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है । मैं फिर कह रहा हूँ मैं इनको बुलाकर विभाग में बैठकर मीटिंग कर लेता हूँ ।

अध्यक्ष : वास्तव में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है एक बार माननीय मंत्री जी के साथ सभी कागजातों को लेकर के बैठ लें और बैठने के बाद माननीय मंत्री जी समुचित कोई न कोई निर्णय और निष्कर्ष निकालने का काम करेंगे जैसा कि वे कह रहे हैं ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमलोग बैठने के लिए तैयार हैं तो मंत्री महोदय एक टाइम फिक्स कर दें कि आपलोग बैठिये और हम इतना दिन के अंदर कर देंगे ।

मो0 जमा खान,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन खत्म हो जाय तो सदन खत्म होने के बाद हमलोग बैठ जायेंगे, नहीं तो परसो ही 2 बजे बैठ लें ।

श्री राजेश कुमार : मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ परसो बैठ जाऊँगा और इनसे संबंधित जितने भी ये लोग हैं उनको भी शामिल रखा जाय ।

मो0 जमा खान,मंत्री : इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सदन खत्म हो जाता है उसके बाद डेट तय कर लेते हैं और तमाम जो हमारे सदस्य हैं बैठ जायेंगे हमलोग ।

श्री राजेश कुमार : थैंक्यू सर ।

अध्यक्ष : अच्छा रहेगा कि सदन के समापन के बाद इत्मीनान से माननीय अन्य सदस्यों को भी जो आप बोल रहे हैं सम्मिलित करके आप माननीय मंत्री स्तर पर एक बैठक करें और बैठक में गंभीर मामले पर वार्त्ता करके किसी समुचित निष्कर्ष पर आपलोग पहुंचेंगे ।

श्री राजेश कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ग्राम रक्षा दल जो था वर्ष 2001 से 2005 तक उसका कार्य मुखिया जी के द्वारा लिया जा रहा था । मैं भी वर्ष 2001 से लेकर 2015 तक तीन टर्म मुखिया ग्राम पंचायत में रहकर सेवा दिया हूँ लोगों को, महान जनता को । ग्राम रक्षा दल का गठन होना चाहिए चूंकि 2005 के बाद उसको हटा दिया गया है । मैं

आपके माध्यम से एक जानकारी दूंगा माननीय मंत्री महोदय को, सरकार को बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा कि पहले जो पंचायत सचिव हुआ करते थे वह जो ग्राम रक्षा दल में काम करते थे उसी को सरकार पंचायत सचिव बनाती थी और अभी भी वह पंचायत सचिव बहुतों जगह काम कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि जब इतनी बड़ी समस्या का हल दिया गया है पंचायत सरकार भवन बनाया गया है पंचायतों में तो उसमें किसी को कोई खबर पहुंचाना है, किसी को बुलाना है उसमें तो अनेक तरह का काम होता है तो उस भवन में एक ग्राम रक्षा दल तो होना ही चाहिए । पहले ग्राम रक्षा दल रात्रि प्रहरी के रूप में भी काम करते थे । इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि इसकी व्यवस्था सरकार करे और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस व्यवस्था पर जरूर विचार किया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय प्रश्नकर्त्ता और पूरक के रूप में माननीय सदस्य ने भी आपके ध्यान को आकृष्ट करने का काम किया है । जो बैठक आप करेंगे तो इन तमाम लोगों को बैठाकर के आप विचार करेंगे । इसमें सरकार को समीक्षोपरान्त निर्णय लेने का जो अवसर आयेगा तभी जब नियम कहेंगे और नियमानुसार कार्रवाई आप करेंगे ।

मो0 जमा खान,मंत्री : ठीक है अध्यक्ष महोदय, सदन के तुरंत बाद हमलोग बैठ लेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : सभी दल के नेताओं को बुलाइयेगा ?

मो0जमा खान,मंत्री : सभी लोग रहेंगे ।

अध्यक्ष : सभी लोग कैसे रहेंगे ?

मो0 जमा खान,मंत्री : जो नेता लोग हैं पार्टी के उन्हीं को मैं बोल रहा हूँ ।

अध्यक्ष : हां, उन्हीं को रखिये । ये आप बोल रहे हैं सो बोल दीजिए, ठीक है ।

मो0जमा खान,मंत्री : जिनका सिग्नेचर हस्ताक्षर है ध्यानाकर्षण में वे ही लोग रहेंगे और हमलोग बैठकर बात कर लेंगे । जिस दिन सदन खत्म होता है उसके दूसरे दिन हमलोग बैठ जायेंगे ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, कोरोना काल में भी उनकी सेवा ली गयी है तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और उनको मानदेय तो निश्चित रूप से देना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नों को उन्होंने सुना भी, जवाब भी दिया और जो ध्यानाकर्षण में हस्ताक्षरित सभासद हैं उन तमाम माननीय सदस्यों को सदन के बाद अपने स्तर पर बैठाकर के विचारोपरान्त नियमानुसार जो

उचित होगा वह कार्रवाई सरकार करेगी । आप माननीय मंत्री जी से मिलकर बात कर लीजिएगा ।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें, अनुपस्थित हैं ।

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/पुलकित/02.03.2023

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-205 के अनुसरण में बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2022 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2022 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2022-23 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में, मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा । इसके लिए दिनांक 02 मार्च, 2023 एवं 03 मार्च, 2023 की तिथि निर्धारित है । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	78 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	77 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	45 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	12 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	04 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	02 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	01 मिनट
कुल	-	240 मिनट

माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया, उस पर मैं यही कहूंगा कि - बधाई

उन्हें जो सोकर बे-खबर नींद में और देख रहे कोई मीठा सपना, यह आवाज उनके खर्राटों की आवाज है । महोदय, इस बजट ने आज फिर से सिद्ध किया है कि जब जनादेश का अपमान कर बहुमत का चीरहरण करते हुए स्वार्थ और अवसर वाद के साये में सत्ता के लिए गठजोड़ होता है तो जनता के साथ छल के साथ सिवा नतीजे में कुछ नहीं मिलता है । माननीय वित्त मंत्री जी ने चिर-परिचित अंदाज में शब्द जाल बुनते हुए बजट भाषण में सदन को बताया कि 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुनी हो गयी है । तीन गुनी, यह बड़े गर्व का विषय है। महोदय, मैं इस बात से सहमत हूँ लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह चमत्कार आखिर कैसे संभव हुआ ? उस पर प्रकाश नहीं डालें, उस पर थोड़ा डिटेल में अगर ये बताते तो ज्यादा अच्छा होता । वित्त मंत्री जी, सच को स्वीकार करना भविष्य को सुधारने के बराबर है और यह कठिनाई हो सकती है लेकिन हम सच नहीं स्वीकारेंगे तो जो बिहार के विकास का सपना है वह साकार कैसे होगा ।

''जिंदगी की कठिनाइयों में भाग जाना आसान होता है,
जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है ।
डरने वालों को नहीं मिलता है कुछ जिंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है ।''

आज दुर्भाग्य से हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि राज्य के अपने स्रोत से राजस्व प्राप्ति सीमित रही है । महोदय, राजस्व का अन्य स्रोत केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से रही है । इस सत्य को सदन को बताना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । महोदय, याद दिलाना होगा कि इनके नये सहयोगी कांग्रेस शासित केन्द्र सरकार के दौर में 13वें वित्त आयोग तक केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी काफी कम थी । पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने राज्यों को उनका वाजिब हक नहीं दिया लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया, इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा कर संग्रहों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दी गयी । महोदय, 10 प्रतिशत का उछाल आया, इसको भी स्वीकारना चाहिए, सदन को बताना चाहिए । महोदय, इसका लाभ बिहार को मिला है । सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिला है, जिसकी वजह से बिहार राज्य के बजट के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है । महोदय, राज्य सरकार के अपने स्रोत से आय लगभग 25 प्रतिशत के आसपास रही है । मात्र 25 प्रतिशत के आसपास अपने स्रोत से इनकी आय है लेकिन केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी ही वह कारण है जिससे राज्य सरकार खर्च बढ़ा सकी है । केन्द्रीय करों

के कारण ये खर्च बढ़ा सके हैं । इस बजट में भी राज्य सरकार के अपने स्रोत से आय बढ़ाने में कोई नये प्रावधान नहीं दिखते हैं । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी यह जान लीजिये कि आदरणीय मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में लिये गये नीतिगत परिवर्तनों का सीधा लाभ बिहार को मिला है । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप शायद भूल रहे हैं कि 09 अगस्त से पहले भी कई बार इस ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार की आप तारीफ कर चुके हैं । प्रधानमंत्री जी के मंच से भी आपने उनको बधाई दी है । महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई0एम0एफ0) के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2021-22 में औसत आर्थिक आय वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही है । इसी वर्ष देश की औसत आर्थिक आय वृद्धि 1.7 प्रतिशत अनुमानित रही है । साथ ही वित्त मंत्री जी ने इस तथ्य पर भी पर्दा डाल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक जैसी तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं ने आने वाले दशक को भारतीय अर्थव्यवस्था का दशक कहा, यह देश के लिए गौरव का विषय है । इस बात पर हमारे साथ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सदन में बैठे तमाम लोगों को भारतीय होने के नाते गर्व होना चाहिए । महोदय, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि राज्यों के आर्थिक विकास दर का अनुमान आई0एम0एफ0 नहीं लगाती है । इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 प्रतिशत बतायी है । यह आंकड़े राज्य सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा बनाये जाते हैं । अब आप ही बताइये, आई0एम0एफ0 के अनुमान की तुलना राज्य सरकार के निदेशालय के आंकड़ों से की जा रही है । ये दोनों आंकड़े दो अलग स्रोत से लिये गये अनुमान हैं इसलिए यह तुलना बे-मेल है, माननीय वित्त मंत्री जी स्पष्ट करेंगे । महोदय, बिहार के विकास के जो आंकड़े दिये गये हैं वे त्वरित अनुमान होते हैं जो वास्तविक आंकड़ों से अलग ही होते हैं जिसमें पहले से भी काफी परिवर्तन होते रहे हैं । उदाहरण के लिए राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में बिहार के वर्ष 2020-21 के विकास दर का त्वरित अनुमान 2.5 प्रतिशत बताया गया है । उसी वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में यह विकास दर रिवाईज होकर -3.5 प्रतिशत बतायी गयी है । राज्य और देश का विकास हो, यह हम सभी के लिए गौरव की बात है लेकिन महज आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होनी चाहिए बल्कि सही आंकड़ों के साथ बिहार की तस्वीर सामने रखी जानी चाहिए ।

(क्रमशः)

टर्न-11/अभिनीत/02.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल (क्रमशः) : महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर जो बातें रखी हैं, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । जीएसटी कर प्रणाली सभी राज्यों की सहमति से लागू की गयी थी । इसे सहकारी संघवाद की सफलता के रूप में देखा जाता है महोदय । जीएसटी लागू होने के समय यह तय था कि यह प्रावधान केवल पांच वर्षों के लिए है । यह निर्णय सभी राज्यों की आम सहमति से लिये गये, उसमें भी कुछ छिपाया नहीं गया है । महोदय, यह जीएसटी परिषद् में लिये गये निर्णय हैं जिसमें सभी राज्यों की भूमिका है । सभी ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है । महोदय, वित्त मंत्रीजी ने बताया कि राज्य के राजस्व घाटे को कोविड-19 प्रभावित वर्ष 2020-21 के 11 हजार 335 करोड़ रुपये से कम करते हुए वर्ष 2021-22 में 442 रुपये पर लाया गया । महोदय, कोविड-19 प्रभावित 2020-21 में केंद्र सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत खर्च बढ़ाने की गुंजाइश मुहैया कराई थी, इसको भी स्वीकारना चाहिए, जिस कारण यह बढ़ा हुआ घाटा भी तय सीमा के भीतर रहा था । महोदय, अगले वर्ष हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री तारकिशोर जी के कुशल नेतृत्व ने इसे कम करते हुए 2021-22 में 422 करोड़ पर लाया गया था महोदय, यह कुशल प्रबंधन का नतीजा था । इस सफलता की चर्चा माननीय वित्त मंत्रीजी ने जरूर की है लेकिन हमारे सकारात्मक योगदान को बड़ी चतुराई से छुपा लेते हैं । श्रेय देने की इनकी मंशा कतई नहीं रहती है, श्रेय लेने की मंश रहती है, हृदय को थोड़ा उदार इनको बनाना पड़ेगा ।

महोदय, हम जिस संगठन, जिस संस्कार, जिस स्वभाव से आज यहां पहुंचे हैं, यह हमें अनुशासित रहने की सीख देती है । यह हमारे क्रिया-कलापों में दिखता है महोदय । अनुशासित वित्तीय प्रबंधन हमारे वित्त मंत्रियों की देन है और एक बात कहना चाहेंगे कि अनुशासित वित्तीय प्रबंधन ही किसी राज्य की विकास गाथा की रीढ़ होती है महोदय । वित्तीय अनियमितता इस विकास गाथा की सबसे बड़ी बाधा होती है । महोदय, याद कीजिए 2005 से पहले राज्य की वित्तीय हालत कैसी थी । याद कीजिए 2005 के पहले राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी थी । अराजक वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश में कुख्यात था । महोदय, 2005 की वित्तीय स्थिति अराजक वातावरण के लिए पूरे देश में कुख्यात था, बदनाम था महोदय 2005 के पहले...

श्री शकील अहमद खां : माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य खड़े हुए हैं और कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, पूरी बात सुनी जाय । बीच-बीच में ये खड़े होंगे..

अध्यक्ष : ये कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट, तुरंत बैठ जायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, तो समय हमारा उतना जोड़कर बढ़ाना पड़ेगा जितना समय आप उनको दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट में, एक मिनट में, ज्यादा नहीं ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कल मुख्यमंत्री और फाइनांस मिनिस्टर का भाषण सुना है कि नहीं ? क्यों मैं यह कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि केंद्रांस का जो पैसा है वह स्टेट को देना केंद्र की जिम्मेदारी है और अगर उस जिम्मेदारी से वह बचती है तो इसका मतलब है कि राज्य के साथ खिलवाड़ और बेइमानी कर रही है, नम्बर वन । नम्बर टू, 2004 से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण किया जाय ।
नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सभी पार्टी को मौका दे रहे हैं, अपने विषय को रखें, बीच में भटकाने का खेल नहीं होना चाहिए, बरगलाने का, भरमाने का खेल नहीं होना चाहिए । आप सबको तो बहुत ही अच्छे से याद होगा, यहां तक कि उस समय की व्यवस्था में यहां उपस्थित लोग गवाह ही नहीं बल्कि भागीदार रहे हैं ।..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : उस समय की सरकार के खजनों, महोदय 2005, उस समय की सरकार की खजानों की लूट-खसोट में सरकार लगी हुई थी, सरकार लगी हुई थी महोदय, परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री जेल की हवा खा रहे हैं । जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस दौर में 2005 की हमारी पार्टी के वित्त मंत्री ने जो एनडीए की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हमारे वित्त मंत्री ने अथक प्रयास से राज्य में वित्तीय अनुशासन का माहौल बनाया लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके और आपके भतीजे की जोड़ी कुछ दिन और सलामत रह गयी तो बिहार में पुनः वित्तीय अराजकता का माहौल व्याप्त हो जायेगा महोदय । बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्रीजी आप तूफानों से कश्ती निकालकर लाये थे, वित्तीय अराजकता से मुक्ति दिलाया था । आपकी जोड़ी और माननीय सुशील मोदी की जोड़ी ने खजाना लूटने वालों से मुक्त कराया था और फिर उसी

की गोद में खजाना को पहुंचा दिया है और आपने तो उसके उत्तराधिकारी की भी बात कह दी है ।

(व्यवधान)

महोदय, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे पूर्व मंत्री शाहनवाज जी दिन-रात एक करके राज्य की छवि सुधारने का सफल प्रयास किये थे जिसके सकारात्मक परिणामों की चर्चा उनको बिना धन्यवाद दिए वित्त मंत्रीजी कर रहे थे। चर्चा कर रहे थे कि हमने इंडस्ट्रीज लगाये, बोटलिंग प्लांट से लेकर इथेनॉल प्लांट की भी चर्चा किये, किसके रीजन में लगा ? मुख्यमंत्रीजी का ठीक है नेतृत्व था लेकिन उद्योग मंत्रीजी की भी पहल और मेहनत थी, शाबासी तो मिलनी चाहिए थी। राज्य में इथेनॉल प्लांट में जो निवेश हुआ महोदय किसके द्वारा लाया गया ? यहां यह ध्यान देने की बात है कि यह कैसे हुआ । आपको बतला दें कि इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार द्वारा हर राज्य के लिए कोटा निर्धारित किया गया था महोदय, जिसके कारण से केंद्र सरकार द्वारा हमारे राज्य में निवेश के अवसर दिए गये और निवेशक किसी अन्य राज्य में जाने को स्वतंत्र होते हैं महोदय । लोगों को लगा एन0डी0ए0 की सरकार है, वातावरण अनुकूल है, मुख्यमंत्रीजी श्रद्धेय अटल जी की गोद से प्रशिक्षण लेकर आये हैं, सुशासन स्थापित करने वाले लोग हैं तो निवेशक आकर्षित हुए लेकिन फिर से, जब से जंगल राज का वातावरण बना, जिसको जनता राज्य मुख्यमंत्री कहने लगी और ठहर गये निवेशक महोदय । निवेशक आ नहीं रहे हैं, निवेशक आते तो रोजगार का अवसर मिलता और बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती । निवेश ठहर गया बिहार में महोदय । आज मुख्यमंत्रीजी जिसके शरण में बैठे हैं, उसी कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उसने बिहार के साथ भयानक भेदभाव किया था । इस बात से स्वयं मुख्यमंत्रीजी भी सहमत रहे हैं लेकिन अवसरवादिता की राजनीति की अपनी मजबूरियों के कारण आज वह मौन रहने को विवश हैं । वह दौर था जब कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश बना रखा था । कांग्रेस के लोगों ने बिहार के विकास के लिए कभी कदम नहीं उठाया । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू नेहरू जी के आंख में आंख डालकर बात करते थे और बिहार में इंडस्ट्रीयल वातावरण बनाने के संकल्प को साकार किये थे । लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रहा, कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही, उस पीरिएड के बाद आजतक बिहार में इंडस्ट्रीयल वातावरण बनाने से क्यों बिहार रूका रहा, यह भी बताना चाहिए । महोदय, वित्त मंत्रीजी आपको याद आ चुका होगा कि वह दौर कौन सा था, अगर जान-बूझकर नादान बन रहे हैं तो हमको याद दिलाना है ।

कांग्रेस शासित पूर्व सरकार ने भाड़ा समानीकरण की नीति लायी थी । भाड़ा समानीकरण की नीति, जिसके तहत तत्कालीन बिहार के खनिज और प्राकृति संसाधन..

(व्यवधान)

महोदय, नये सदस्य सुनने का भी प्रयास करें कि जो भाड़ा समानीकरण की नीति लायी गयी थी वित्त मंत्री जी प्रकास डालेंगे, उस नीति में क्या था ? कांग्रेस की यह नीति थी भाड़ा समानीकरण, उस नीति के तहत बिहार से खनिज और प्राकृतिक संसाधन केंद्र सरकार के खर्च पर अन्य राज्यों को उपलब्ध कराया गया और बिहार न केवल अपने संसाधानों को खोता रहा बल्कि निवेश से भी वंचित रहा, जिससे बिहार को लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ । ..क्रमशः..

टर्न-12/हेमन्त/02.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल(क्रमशः) : बताना चाहिए ऐसा क्यों हुआ झारखंड साथ में था । महोदय, हद तो तब हो गयी कि शोषण की यह प्रक्रिया 1952 से यह शोषण, महोदय, शांति बनाये रखें, सबको बोलने का अवसर है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें । माननीय नेता प्रतिपक्ष बजट में जो खूबी है, अपनी दृष्टि से उस खूबी को भी रखने का काम करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी संरक्षक हैं । विपक्ष का काम है बजट की खामी को दिखाना, बजट की कमी को बताना । खूबी तो सरकार के लोग झूठी पीठ थपथपायेंगे ही । महोदय, यह जानकारी होनी चाहिए सदन को, यह शोषण की प्रक्रिया जो कांग्रेस के शासन में शुरू हुई थी 1952 से 1993 तक जारी रही । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस कांग्रेस की गोद में आप बैठे हैं उसके काले कारनामों को आप कैसे धोयेंगे, जिसने बिहार से सौतेला व्यवहार किया, बिहार को पीछे ले जाने में अहम भूमिका निभाई । इसलिए मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान रखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो इतिहास को याद नहीं रखते, उनको इतिहास को दोहराने का दंड मिलता है । आज आपकी सरकार बिहार को बरगलाने का, ठगने का और वही इतिहास दोहराया जा रहा है और मैं कहना चाहूंगा कि सत्य से मुंह मोडियेगा, तो समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध । बिहार के साथ हुए गलत कार्यों को अगर दबाने का प्रयास कीजिएगा, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा ।

महोदय, हम रोजगार के मामले पर आते हैं । बहुमत की चोरी कर स्वार्थ और अवसरवाद का सहारा लेकर यह सरकार जब बनी थी, तब उप मुख्यमंत्री जी ने पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देने का सब्जबाग दिखाया । यह इन्हें भलिभांति पता था कि इस वादे का कोई आधार नहीं है । लेकिन हवाहवाई...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । आपको भी अवसर मिलेगा, आप भी बोलियेगा । अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : ये वामपंथी लोग हैं । जो देश को नहीं, बिहार को शासन में ले गये थे । क्या बोलेंगे ये लोग ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, कभी-कभी हमने यूं ही जीत को बहलाया है, जो बातें खुद नहीं समझे औरों को समझाया है । वही हाल इन लोगों का है । औरों को समझाया है, लेकिन खुद समझने के लिए तैयार नहीं हैं । जो वामपंथी लोग हैं विकास के प्रति ये लोग समर्पित नहीं हैं । महोदय, हद तो तब हो गयी जब सरकार के बनने के महीनों बाद भी आज तक उप मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से दस लाख नौकरियों की बहार तो नहीं आयी, लेकिन वित्तमंत्री अपने बजट भाषण में वही सब्जबाग फिर से दिखाने का प्रयास किये । लेकिन समय के साथ घिस-घिस का आंकड़ा दस लाख, महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी दस लाख के आंकड़े को चार लाख पर ले आये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप शांति बनाये रखें और माननीय प्रतिपक्ष, आप किसी दल का नाम न लेकर आप बजट पर बोल रहे हैं, बजट पर ही बोलें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : बजट पर ही बोल रहे हैं महोदय । दस लाख नौकरी का वादा...

अध्यक्ष : अब आप किसकी इजाजत से खड़े हो गये ? बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : ये शब्दों के जाल में फंसाकर स्पष्ट हो गया कि नौकरी का एक धोखा है, यह एक फरेब है । दस लाख नौकरी कैसे देंगे ? महोदय, गंभीरता से सुनें । जब हम बजट प्रावधानों को देखते हैं, तो वेतन मद में मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । बजट मद में मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि है वेतन मद में । हम सब अवगत हैं कि सरकारी नौकरियों में महंगाई भत्ता में वार्षिक वृद्धि दी जाती है । महोदय, इस मद में हर वर्ष लगभग दस प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि होती है । वर्तमान में जो सरकारी नौकरी में हैं उनके वेतन के लिए

भी बजटीय प्रावधान कम पड़ रहे हैं । ऐसे में नये रिक्त पदों को भरे जाने का जो मोहपाश फेंका जा रहा है उसके लिए पैसे का प्रावधान कहां किया गया ? इस पर वित्तमंत्री जी बतायें । देश में बेरोजगारी 12 प्रतिशत और बिहार में बेरोजगारी 20 प्रतिशत, बजट के किस हिस्से में आपने बजट का प्रावधान किया है । सदन को स्पष्ट बताया जाय महोदय । महोदय, जो लोग बोल रहे हैं इनके नेता यहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में फकरा पढ़ते थे । वह पढ़ते थे पढ़ाई, कमाई, नौकरी, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार । कहां गया ये सारा ? यह फकरा कहां गया? महोदय, हमारी जुबां सत्य की इन बातों पर स्पष्टता की बाट जोह रही है । आप जुबां को भरमा रहे हैं । आपने जो प्रावधान ही नहीं किया, मात्र चार प्रतिशत की वृद्धि है । तो कैसे दस लाख नयी नौकरी देंगे और उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया ? बिहार की जनता, बिहार का नौजवान जानना चाहता है । यह धोखा है नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा है । महोदय, सरकार अपने ढुलमुल रवैये से बाहर निकलकर बिहार की जनता और सदन को यह बताये कि किन-किन पदों पर, किस-किस तारीख को नियुक्ति की जायेगी । यह स्पष्ट बताइये, भ्रमाये नहीं, राजनीतिक मुद्दा न बनायें । बार-बार हमें सुनने को मिलता है कि सरकार सुनवाई, कार्रवाई कर रही है । महोदय, बाहर हमारे करोड़ों नौजवान साथी कार्रवाई की इंतजार में बैठे हैं । आज आपने देखा, आज तमिलनाडु में....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आप अपने स्थान पर बैठिये । आपको पुकारा जायेगा, आप बोलियेगा । माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी अपने स्थान पर आप बैठ जायं । नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, आप इन्हें बोलने दें । मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो समय बर्बाद हो रहा है, हमारा समय बढ़ाना होगा । विपक्ष की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है । महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतने हमारे नौजवान दूसरे स्टेट में रोजगार के लिए गये हैं और रोजगार की तलाश में उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी । महोदय, एक दर्जन से ज्यादा लोगों के लिए तमिलनाडु में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कब तक हमारा बिहार का बेटा इस तरह से दूसरे राज्य में अपमानित होगा और उनको मौत के घाट उतारा जायेगा । 32 साल, 33 साल से छोटे भाई, बड़े भाई की सरकार थी । क्या नीति आपने बनायी ? किस पॉलिसी के कारण बिहार से इन नौजवानों का पलायन रोकने का आपने कदम उठाया ? यह वित्तमंत्री जी को बताना चाहिए । महोदय, विश्वविद्यालय में 4,638 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी थी । हमारे

वित्तमंत्री जी जब शिक्षामंत्री थे, उन्हीं के पीरियड में शुरू हुआ था । महोदय, आज दो वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक बहाली नहीं कर पायी । दुर्भाग्य की बात है कि यह बहाली भी बिहार के विश्वविद्यालयों की मान्यता को बरकरार रखने के लिए न्यूनतम जरूरी पदों पर की जा रही थी ।

(क्रमशः)

टर्न-13/धिरेन्द्र/02.03.2023

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मान्यता रद्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया, क्यों ऐसा हुआ, इस पर भी सरकार को जवाब देनी चाहिए कि आज विश्वविद्यालयों की मान्यता पर खतरा उत्पन्न होने का क्या-क्या कारण रहा, किसकी जिम्मेवारी रही, महोदय, यह तय होना चाहिए । महोदय, एक तरफ विद्यालयों के नये शिक्षक की बहाली की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे युवाओं पर लाठियों की बौछार होती है, उसको पीटते हुए बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए विवश करते हैं और रोटी की प्रथा को लेकर जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहाँ भी अपमानित होकर पीट-पीट कर मौत के घाट उतरे जाते हैं । महोदय, किसकी जिम्मेवारी है ?

महोदय, पहले से बहाल शिक्षकों को कब तक समान काम के लिए समान वेतन की माँग को पूरा कर पायेंगे, इसी जगह से नेता प्रतिपक्ष बड़े तेज आवाज में बोलते थे, आज मुँह बंद क्यों हो गया । कुर्सी के लिए इतना मौन, इतना समर्पण, बिहार के नौजवान को आस जगी थी लेकिन ये अपनी रोजगार पाने के लिए बिहार के नौजवानों की आवाज को खत्म कर दिये, पूरा बिहार आज शर्मसार हो रहा है, महोदय । कथनी-करनी में कहीं समरूपता नहीं है उप मुख्यमंत्री जी का, ऐसी विवशता क्यों ? उप मुख्यमंत्री जी, आपको तो चुनावी वादा भी अब याद नहीं है, सभी के चुनावी वादे को निकालकर अब हम लोगों को दिखायेंगे और बतायेंगे कि क्या-क्या वादा किये थे और उस चुनावी वादे में कितना खरे उतरे थे । क्या सत्ता के सुख में डूबकर वह अपने वादों को भूल गए, संविदा पर बहाल लोगों को अनिश्चितता के साये में कब तक नियमित करेंगे, अब क्या उनके भविष्य को भी अधर में लटकायेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी जब कैबिनेट में मंत्री बनने का अवसर दिये थे, आप जब बोलते थे कि संविदा कर्मी अनुभवी हो गए हैं, संविदा कर्मी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आप ही बोलते थे, हम आपको याद कराना चाहेंगे कि उस संविदा कर्मी को क्यों नहीं परमानेंट करते हैं, क्यों नहीं उसको आप महत्व देते हैं, नौकरी में प्राथमिकता देते हैं ? मुख्यमंत्री जी, युवाओं के सपनों को तोड़ने वाले अपने विरासत और अभिभावक पर कैसे गर्व महसूस करेंगे, यह भी

आपको बताना पड़ेगा । इसलिए एक बार फिर अपनी युवा शक्ति से अनुरोध करते हैं कि सरकारी नौकरी पर किए गए वादे को यथाशीघ्र पूरा करने का वित्त मंत्री जी आपकी क्या नीति है, क्या बजट में प्रावधान है ? ये बतायें ।

महोदय, सत्ता में बैठे लोग बहाली की घोषण के लिए चुनाव की तिथियों के इंतजार में होंगे लेकिन उनके इस बर्ताव से पैदा होने वाली नकारात्मक असर से हमारे युवा साथी हर दिन जूझ रहे हैं । महोदय, कितने बलिदान लेंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन में अपराधियों के शरणस्थली में प्रवेश कर रहा है, कोई दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है । महोदय, आज कोई शराब माफिया के दरबार में जाकर 500-1000 रुपये की नशीली दवाओं को बेचने के लिए विवश हो रहा है क्योंकि रोटी की तड़प और रोटी की भूख उन बेरोजगारों को गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश कर रही है, कौन जिम्मेवार है, इसके लिए क्या प्रावधान है ? वित्त मंत्री जी बतायेंगे ।

महोदय, सदन को गंभीरता से लेना चाहिए । बजट में कृषि और किसानों को लेकर जो बड़ी-बड़ी बातें की गई हैं उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इनको बिहार में किसानों में खुशहाली और संवृद्धि की लहर दिख रही है । इनको लग रहा है कि यहाँ के किसान समृद्ध हो गए, इनकी लाफेबाजियों को सुन-सुन कर तो यही ख्याल आता है क्योंकि बजट में उनके लिए विशेष कुछ नहीं किये हैं।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के लिए कुछ कहना चाहूँगा- जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाइयों का हल क्यों नहीं निकलता है। हम समाधान यात्रा पर भी गए, है जिससे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसी बिखरी किस्मत आज किसान की । आज किसानों के किस्मत को, मुख्यमंत्री जी आपको तो याद ही होगा, हर थाली में बिहार का व्यंजन होगा । क्या हुआ, कहाँ ये बोल भी बंद हो गई, क्यों ? विचार करें । महोदय, इन्होंने कहा था इसी सत्र में कृषि रोड मैप-4 प्रस्तुत किया जायेगा, उस नये रोड मैप में क्या-क्या नयी कलाबाजियाँ होंगी, वह तो हम सब देखते हैं, लगता है कि कुछ मुद्दे पर आप जानबूझकर सोते हुए भी मीठे सपने देख रहे हैं, हम उस पर आपको जगाना चाहते हैं । महोदय, इसी महागठबंधन के कृषि मंत्री सुधाकर जी थे, वे बैठे होंगे माननीय सदस्य । रोड मैप की उपयोगिता सहित कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उठाये थे उसकी प्रतिक्षा में सदन के साथ-साथ बिहार की समस्त जनता भी है, उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए, उसका भी समाधान करना चाहिए । नया कृषि रोड मैप जो होगा वह होगा लेकिन इस बजट के प्रावधानों में कृषि के लिए 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गयी है । बिहार कृषि राज्य है

जहाँ 1.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गयी है । कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को देखा जाय तो उसमें 19 प्रतिशत की कटौती की गयी है, महोदय, बढ़ाने की बजाय कटौती कर दी गयी है, वित्त मंत्री जी को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए । महोदय, कृषि और कृषकों को छलते हुए ये जो सब्जबाग दिखा रहे हैं, कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आँखें मूंदे हर दिन नये-नये सपने दिखा रहे हैं, इससे क्या अर्थ निकलता है ? वित्त मंत्री जी, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली हो तो बताइये साहब कैसे कह दूँ कि फाल्गुन की धूप नशीली है । कैसे किसान फाल्गुन मनायेगा, आपकी बजट ने किसान को रूला दिया । सरकार में बैठे लोगों से आग्रह करेंगे कि कुंभकर्ण की नींद से जागिये, सपनों की दुनिया से निकल कर सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल, सही जगह पर, सही काम में कीजिये, हमारे अन्न देव किसानों के लिए भी कुछ प्रावधान ईमानदारी से कर दीजिये ।

महोदय, राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बालू खनन है जो कि मिट्टी में छुपे सोने की तरह है । भ्रष्टाचार में आखंड डूबी सरकार ने बालू माफियाओं को खुली छूट दे रखी है, बजट से ऐसा संदेश दिया गया है कि यहाँ से आय बढ़ाने की सरकार की कोई भी मंशा नहीं है । सरकार ने अपने स्रोत से राजस्व में वृद्धि केवल छः प्रतिशत की है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बजट पर बोल रहे हैं तो आप टोका-टोकी न करें । माननीय नेता प्रतिपक्ष, निराश नहीं होना चाहिए, निराश होने से पौरुष मर जाता है, इसीलिए कहा गया है कि नर हो, न निराश करो मन को....

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप कंस्ट्रक्टीव बात कीजिये, केवल डिस्ट्रक्शन से काम नहीं चलने वाला है । बजट के बारे में बतलाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आप तो अपनी जिंदगी के अंतिम पायदान पर बैठे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमलोगों को उत्साहित करेंगे । आपकी आशा भरी निगाह जब हमलोगों पर पड़ेगी तो नौजवान लोग उत्साहित होंगे और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि निराश नहीं होने देंगे, आपको बता देते हैं ।

अध्यक्ष : मैंने कहा कि आप निराश नहीं होइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप लोग निराश हो रहे हैं, उम्मीद की किरण इधर बैठी है ।

अध्यक्ष : सरकार विकास करने के लिए तत्पर है, इसलिए आप निराश मत होइये । आप निराशा भरा भाषण दीजियेगा तो सदन के माननीय सदस्य...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, डिस्टर्ब न करें, जितना मिनट का समय हमारा गया, उतना समय मेरे माननीय सदस्यों के लिए बढ़ाना पड़ेगा ।

महोदय, आज बालू खनन से बहुत सारा राजस्व राज्य सरकार को मिल सकता है लेकिन बालू खनन का माफियागिरी सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं । महोदय, खनन मंत्री जी बैठे हैं और बड़े नजदीक से जानते हैं कि किन माफियाओं के द्वारा सत्ता के शीर्ष तक माल जा रहा है लेकिन राजस्व नहीं आ रहा है । इस पर लगाम लगाया जाय तो राजस्व बढ़ेगा, यह सकारात्मक सुझाव है । थोड़ा उधर भी देख लें ताकि उन पर भी प्रभाव पड़े ।

...क्रमशः...

टर्न-14/संगीता/02.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल (क्रमशः) : महोदय, बालू और दारू का खेल निराला है, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है, प्रशासन मतवाला है । महोदय, मंत्री जी बैठे हैं आपके माध्यम से कहूंगा कि बचाइए बालू और दारू से और बिहार के राजस्व को बढ़ाइए । महोदय, ग्रामीण विकास की हम बात करें तो बिहार की आत्मा आज भी गांवों में बसती है लेकिन सरकार शायद यह बात भूल गई इसलिए ग्रामीण विकास, सहकारिता, श्रम संसाधन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में बजटीय प्रावधानों में कमी की गई है महोदय, कम कर दिया गया, मजदूरों से जुड़ा हुआ, श्रम मंत्री रहे थे और इस तरह से जो व्यवस्था बनायी जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है दुखद है महोदय ।

महोदय, आज मनरेगा की बात कर रहे हैं कितना फॉल्स कार्ड निकला, कहां जाता था पैसा, कौन जिम्मेवार है तय करे सरकार, 6-6 लाख फॉल्स कार्ड कैसे, इस बिहार में कैसे यह सब हो रहा था, गरीबों का पैसा लूटा जा रहा था ? महोदय, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का हम क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत का जब देश के प्रधानमंत्री जी संकल्प लेकर साकार कर रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते हैं । महोदय, एक झलक पिछले 2 बजट में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के रूप में देखी गई लेकिन प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आज आपको आत्मनिर्भर बिहार शब्द से चिढ़ होने लगा । आप अराजकता और भ्रष्टाचार के निश्चय के साथ सात निश्चय करने जा रहे हैं । जल-जीवन-हरियाली और सात निश्चय, हर घर नल का जल, सदस्य

बैठे हैं दिल पर हाथ रखकर सच बताना चाहिए यह लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, आपकी नीति बहुत अच्छी थी मुख्यमंत्री जी लेकिन 80 परसेंट घर में जल क्यों नहीं पहुंचा, कौन भ्रष्ट लोग हैं जिम्मेवार, क्यों कार्रवाई नहीं हुई इस पर, थोड़ा इसको गंभीरता से वित्त मंत्री जी बतायें क्या फिर से एक बार सर्वे करायेंगे कि कितने घर में जल पहुंच रहा है ? एक बार मुख्यमंत्री जी आप सर्वे करवा लीजिए, हर घर शौचालय, हर घर नल का जल, थोड़ा देख लीजिए सच्चाई क्या है, आप अराजकता और भ्रष्टाचार के निश्चय के साथ सात निश्चय करने चले हैं, इससे बचिए तभी बिहार आत्मनिर्भर होगा। पहले हम थे सूचिता थी, संकल्प था, साथ चलने का भाव था पर आज भय, आतंक और अवसरवाद की जोर पर बना गठबंधन है । यह गठबंधन महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है जहां एकमात्र अभियान है कि हम कैसे जनता को ठग लें और कैसे योजनाओं में मेरा लाभ हो सकता है । महोदय, गठबंधन सात दलों का है । सूर्य अपने प्रकाश के साथ जिस रथ पर चलते हैं सात घोड़ों पर चलते हैं, लोगों को लगा था कि इस प्रकाश से बिहार प्रकाशित होगा, पूरा देश और दुनिया में बिहार का गौरव बढ़ेगा लेकिन महोदय, इनकी न नीयत ठीक है और न नीति ठीक बन रही है । इनके सहयोगी दलों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके घोषणा पत्र की कोई भी बात इस बजट में आयी है, जरा बोलते हुए बता देंगे कि आपके घोषणा पत्र में जो-जो आपने रखा था, एक भी इस बजट में आयी है ?

महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण के बहाने राज्य सरकार और वित्त मंत्री जी ने मुस्लिम तुष्टिकरण का जो खुलेआम प्रदर्शन किया है, वह निन्दनीय है । बजट में बात अल्पसंख्यक कल्याण की होती है लेकिन इसकी सारी बातें घूम-फिरकर मुस्लिम और मदरसों तक सिमट क्यों जाती है, इस पर भी बताना चाहिए । इनके तुष्टिकरण की कोशिश में भी यदि मुसलमानों के विकास का प्रयास दिखता तो हम मान लेते लेकिन यहां न तो मुस्लिम समुदाय के विकास की चिन्ता है न मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की फिक्र है न ही मदरसों के आधुनिकीकरण करने का बोध है, मदरसों में कैसे-कैसे हुनरमंद लोग निकल रहे हैं इससे आज पूरी दुनिया अवगत है । महोदय, इसके लिए संकल्प, साहस, साफ नीयत से हमारी केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी परिवर्तन कर दिखाया लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी ने उस तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सहायता योजना की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी, इससे यही लगता है कि सरकार तलाक की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है । सुधार की प्रवृत्ति नहीं है, तुष्टिकरण की राजनीति है ।

महोदय, गरीबी इंसान के लिए अभिशाप है, बड़े प्रयासों के बाद विकास की मुख्यधारा से वंचित आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए एक सकारात्मक पहल पिछड़े समाज के बेटे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संसद ने की थी । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आप स्पष्ट कीजिए कि आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के उस हिस्से के लिए आपके विचार क्या हैं ? आपका विचार तो हमलोगों के साथ थे तब तो स्पष्ट था लेकिन अब महागठबंधन में क्या विचार है ये स्पष्ट करिए । वित्त मंत्री जी इस पर एक शब्द बोलना भी आपने उचित नहीं समझा, बोलना चाहिए । आर्थिक रूप से बहुत बड़े तबके पिछड़े हैं, समाज के एक हिस्से को गाली देकर उससे वंचित रखकर आखिर आप कैसा समेकित विकास करना चाहते हैं, अपने शब्दजाल के घटाटोप में मुंह न छुपाएं, खुलकर सदन और राज्य की जनता के सामने आप अपने विचार को स्पष्ट करें क्योंकि बिहार में हर बिहारी और हर बिहारी बिहार का बेटा है, सबका समेकित विकास होना चाहिए ।

विशेष राज्य का दर्जा की बात बार-बार उठती है, जब नींद से जागते हैं बोल देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाय । आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सरकार में सहयोगी थे, आपकी रघुराम राजन कमिटी बनी थी, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी मित्र इस कमिटी के सदस्य थे, क्या निर्णय हुआ बता दीजिए, अपने मुंह से सब जानकर भी झूठी बातों में समय क्यों जाया करते हैं, रघुराम कमिटी में आपके मित्र ही तो उस कमिटी के सदस्य थे, क्या निर्णय हुआ था, संघीय ढांचे में सभी राज्यों की अपनी मांग है, वर्तमान केंद्र सरकार विकास में हर तरह से सहयोग को तैयार है लेकिन काम-धाम को छोड़ के बस प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कुछ भी कह देते हैं और जब-जब सोकर उठते हैं विशेष राज्य का दर्जा दुहरा देते हैं ।

महोदय, केंद्र सरकार ने योजना बनाने में राज्य से कुछ बातें सीखी हैं । जो वित्त मंत्री जी ने कहा था, राज्य सरकार के प्रयासों से कई बार केंद्र सरकार द्वारा सराहा भी गया है । महोदय, यह देश राज्यों से बना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की उदारता झलकती है लेकिन वित्त मंत्री जी अपने शब्दजाल के चादर से बाहर निकलकर बताइये कि इस बजट में आखिर नया क्या है ? आपने तो अपने पूर्ववर्ती लोगों की नकल भर की है इसके लिए आप आंखें चुराकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं लेकिन सड़क से सदन तक बिहार की जनता आपकी नीति और नीयत में छिपे खोट को भलीभांति जान चुकी है । मैले हृदय और खोटे मन से आप 7 निश्चय नहीं 70 निश्चय कर लें, हालत नहीं बदलने वाली और अगर आप सोचते हैं कि

आपके सहयोगियों की तरह इस हालत पर मूकदर्शक बने रहेंगे तो आपको भलीभांति यह जता देना चाहते हैं महोदय कि

तानकर भौहें कड़कना छोड़कर मेघ बर्फों से पिघल सकता नहीं
शौक है जिनको जले से प्रेम से हम भी चुपचाप जल सकते नहीं ।

नया बिहार बनायेंगे और नए बिहार की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए नयी संरचना खड़ा करेंगे क्योंकि नोट की चोट बिहार के अंदर नहीं चलेगा, ये जंगलराज वाले लोग जिसको जनता राज बताकर गुन्डा राज स्थापित करने का बिहार में अब नहीं जरूरत है । नया बिहार बनाना है, गौरवशाली बिहार बनाना है । बहुत, बहुत धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव अपना पक्ष रखेंगे ।

टर्न–15/सुरज/02.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी ।

(व्यवधान)

दीपक जब बुझने को होता है तो बहुत भभकता है इसलिये ठीक से बोलियेगा ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उनको कह रहे हैं कि ठीक से बोलियेगा ।

(व्यवधान)

राघवेन्द्र बाबू, मुन्ना जी को कहे कि ठीक से बोलियेगा, ज्यादा भभक कर मत बोलियेगा ।

(व्यवधान)

आप बैठिये पुराना साथी हैं, बैठिये न ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं देख रहा हूं अभी कि पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 24 हजार करोड़ बजट का आंकड़ा बढ़ाया गया है और वह आंकड़ा 2 लाख 61 हजार 885.40 करोड़ किया गया, जो गांव, गरीब और तमाम बिहार के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिये किया गया है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं । अध्यक्ष महोदय, हमलोग गांव में पले, गांव में जन्म हुआ

हमलोगों का, सरकारी विद्यालयों में पढ़े थे, बोरा और चट्टी लेकर के जाते थे स्कूलों में बैठकर के पढ़ते थे । हमलोग सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किये.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य टोका-टोकी न करें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, टोका-टोकी न करें, सुनें बात को । माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को भी सुना जाय । बैठिये न, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

इनकी भी बातों को तो सुना गया, बहुत अच्छे से सुना गया, बहुत अच्छी तरह से नेता विरोधी दल की बातों को सुना गया । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, एक पुरानी कहावत है चोरनी होइहें तो डोलगर होइहें । चार दोस्त मिलकर बैठे थे और एक बिना नाक वाला आ रहा था, वह देखा कि चार लोग नाक वाला है हम तो बिना नाक वाला हैं जाएंगे तो हस देगा । जब उसके नजदीक में आया तो आते-आते कहता है पूर भाई नाक वाला । बिना नाक वाला ही नाक वाला पर हँस रहा था, यही हाल इन लोगों का है । आज जो स्थिति है हमारे बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सर्वांगीण विकास कर रहा है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क के क्षेत्र में हो । लेकिन आज देश की क्या स्थिति बनी हुई है । देश में सारी संस्थाओं को बेचने पर लोग लगा हुआ है, पूरा अराजकता का माहौल है और इमरजेंसी का माहौल लागू किये हुये है और बोलते हैं लोग यशस्वी प्रधानमंत्री । जो बिहार करता है वह देश मानता है । पहले बिहार से शुरू होता है उसको देश मानता है । हमको गर्व है अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर और बात करते हैं ये लोग । अध्यक्ष महोदय, कहा गया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, बाजपेयी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं । बाजपेयी जी ने भी कहा था कि सदन चर्चा की जगह है, यहां शांतिपूर्ण और तर्कपूर्ण चर्चा होनी चाहिये । महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौजवानों को नौकरी और 10 लाख लोगों के रोजगार की बात किये लेकिन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिये, उनको बोलने दीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार की बात हो रही है । तब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे । एक बार भी कोई बी0जे0पी के लोग नहीं बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहां गया । 9 साल में 18 करोड़ नौकरी कहां गया देशवासियों का ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष यह शोभा नहीं दे रहा है । मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किस नियम के तहत आप खड़े हुये हैं वह नियम बताइये । किस नियम के तहत आपलोग खड़े हुये हैं । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आपलोग खड़े हुये हैं बिना अध्यक्ष की इजाजत के, बताइये अगर आपको ज्ञान है तो ?

(व्यवधान)

आप बैठिये, अपनी जगह लीजिये, आप बैठिये, बैठिये आप । बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं । आपके नेता प्रतिपक्ष बोले सब लोगों ने सुना, अब माननीय सदस्य बोल रहे हैं आप उठ-उठ कर टोक रहे हैं ।

(व्यवधान)

संजय सरावगी जी ये आचरण ठीक नहीं है । आप बैठिये, आप जगह लीजिये, बैठिये, मैं कहता हूं कि आप बैठिये । ये बात ठीक नहीं है । नेता प्रतिपक्ष बोले खुब लोगों ने सुना और आपके कोई लोग बोलेंगे उनका भी लोग सुनेगा ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य नेता प्रतिपक्ष कुछ कह रहे हैं सुन लीजिये, कहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सदन में विमर्श का बहुत महत्व है और शांति से सबको सुनना चाहिये । हमारी बातों से आपको किसी तरह से अघात भी लगे तो उसको भी बर्दाश्त करना चाहिये और हमारे कई बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं उनसे भी सीखना चाहिये । कोई बोलते हैं नये लोग या पुराने लोग तो हो सकता है

कि कुछ अच्छी बातें सदन के लिये हो न हो बिहार के हित में हो तो इसको लेना चाहिये । लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये बात विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को संयम रखने की जरूरत है ।

अध्यक्ष : सदन को चलाने के लिये जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की है उससे ज्यादा जिम्मेवारी विपक्ष की है । माननीय सदस्य आप बोलिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि–

''परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुये उनके पर बोलते हैं
अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं ।''

आज पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हुनर बोलता है कि बिहार न्याय के साथ विकास कर रहा है...

(व्यवधान)

फिर देखिये । अध्यक्ष महोदय एक तरफ जहां हम गांव के विकास की बात करते हैं, एक तरफ जहां हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है दैनिक पत्रिका में मैंने देखा है कि शहर ही भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा । ये लोग शहर का विकास चाहते हैं गांव का विकास नहीं चाहते हैं । लेकिन मैं देखता हूं कि आज गांव के जिस गली में चले जाइये, आज सड़कें चकाचक मिलती है, शहर की जैसी स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांव में दिखाई देता है, हर जगह बिजली और पानी की सुविधा हो रही है । यहां तक कि कूड़ा जो जमा करती थी हमारी मां–बहन जाकर के जिसको हम कहते थे कि राख का ढ़ेर लगता था, उसको भी उठाने की व्यवस्था की गयी है और स्वच्छ गांव का निर्माण किया जा रहा है । शहर की बात करते हैं ये लोग लगता है कि गांव से इनका कोई नाता–रिश्ता नहीं है और केवल शहर से मतलब रखते हैं । आज जो स्थिति है शिक्षा की हमको लगता है कि बजट में 40 करोड़ से ऊपर शिक्षा पर खर्चा हो रहा है । पहले क्या स्थिति थी आज हर जगह, हर पंचायत में उच्च विद्यालय खुल गया, अधिकतर पंचायत में 10+2 का विद्यालय बन गया । ताकि गांव में गरीब की बेटी और गरीब का बेटा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके लिये शिक्षक की जो कमी है उसके लिये शिक्षक की बहाली भी हो रही है, उसको भी पूरा किया जायेगा । सड़क की स्थिति सुधर गयी । स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले क्या स्थिति थी, अश्विनी बाबू जब मंत्री थे भारत सरकार में जब वह मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में गये थे उन्होंने कहा था कि इस मेडिकल कॉलेज में जो आयेगा अच्छा आदमी भी बीमार हो जायेगा । उस समय कौन थे मंत्री बिहार के और आज जाकर के देखिये स्वास्थ्य

विभाग में सारे जगह व्यवस्थित ढंग से सारा चीज हो गया । उसके बाद सारी दवाईयां उपलब्ध करा दी गयी है और डॉक्टर लोग भी अब जवाबदेह हो गये हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी ।

(क्रमशः)

टर्न-16/राहुल/02.03.2023

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्रमशः): आज गरीबों का कल्याण हो रहा है हर जगह, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो । सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गरीब की बहू-बेटियां स्कूल नहीं जाती थी कि बदन पर पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं रहता था और आज सरकार ने पोषाक योजना लागू करके उस बदन को ढककर के उसको विद्यालय में भेजने का काम किये हैं । लोग बोलते हैं कि शिक्षा का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ ? अरे आपने तो स्वीकारा दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ ? 10 लाख नौकरी का माननीय मुख्यमंत्री ने 6 महीने पहले बात की और कार्य प्रारम्भ हो गया लेकिन 2 करोड़ नौकरी और 9 साल में 18 करोड़ नौकरी, कोई पूछे अपने प्रधानमंत्री से कि 18 करोड़ नौकरी कहां गई ? कोई नहीं पूछता...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : वो बोलें तो जुमला है । आप देश बेच रहे हो । अडानी कभी अरबों को लेकर भाग जाता है, कभी नीरव मोदी भाग जाता है, कभी कोई लेकर भाग जाता है । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले रेलवे स्टेशन पर हम लोग जाते थे तो 1 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट मिलती थी, सभी साथी जानते हैं और आज 50 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है उसके बाद भी रेल को बेच दिया गया । देश बेचने के कगार पर किये हुये हैं ये लोग । चार आदमी इस देश में, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले हैं । XXX इसके अलावा कोई नहीं है । पूरे देश को गिरवी रखना चाहते हैं ये लोग । अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात होती है मैं कहना चाहता हूं सदन में...

(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कहा है उस बात को प्रोसीडिंग से हटवाया जाय...

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : महोदय, प्रोसीडिंग से हटवाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : यह असंसदीय है इसको प्रोसीडिंग से हटवाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाव को आप समझिये, भावना को न समझिये । मैं देख लूंगा और उसको प्रोसीडिंग से मैं निकलवा दूंगा, मैं प्रोसीडिंग से निकलवा दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, अभी निकलवाइये, प्रोसीडिंग से निकलवाइये ।

अध्यक्ष : वह प्रोसीडिंग से निकाल दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : XXX

अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि उसको प्रोसीडिंग से निकालिये, अब बैठिये आप...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुन्ना जी अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार जो काम कर रही है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप बैठिये, निकाल दिया गया है, बैठिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में भी महिला सशक्तिकरण की तरह काम किया गया है । 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि गांव में गोबर थोपने वाली महिला भी पंचायत, ब्लॉक में जाकर के बैठे और बात करे । जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अब गांव की महिलाएं अंग्रेजी में भी बोलती हैं । पहले हमारी मां, बहन घूंघट निकाल कर के बाहर निकलती थीं आज वें भी कहीं खड़ी होकर किसी से बात करने के लिए तैयार होती हैं यह हमारी सरकार की उपलब्धि है जिसने 50 परसेंट आरक्षण दिया । अध्यक्ष महोदय, सरकारी नौकरियों में भी 35 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया और आज आप देख लीजिये कहीं भी किसी भी थाना में जाकर देखिये तो आज महिलाएं जो हैं पुरूष से कम हथियार लेकर खड़ी नहीं रहती हैं । कहीं-कहीं

तो थाना भी चलाती हैं तो यह महिला सशक्तिकरण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और महिलाओं के विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़, अति पिछड़ा के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू की है । आज इसका नतीजा है कि गरीब का बेटा भी उद्यमी योजना में फॉर्म भरकर के पढ़-लिखकर के 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है जिसमें 5 लाख रुपया उसका माफ हो जाता है और 5 लाख रुपया अनुसूचित जाति को अपना 5 लाख देना पड़ता है और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उसका 1 परसेंट ब्याज लगता है, इससे ज्यादा क्या सुविधा होगी । सरकार अपने बलबूते सीमीत संसाधन में और अपने बलबूते पर सरकार बिहार को आगे बढ़ा रही है लेकिन केन्द्र की सरकार जो कहते हैं 42 परसेंट जो केन्द्रांश बचा हुआ है वह भी देना नहीं चाहती है । जब वर्ष 2014 में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब मुजफ्फरपुर में जाकर कहे कि बिहार को कितना दे दूं 50 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं, अरे लो सवा लाख करोड़ दिया। कहां गया वह सवा लाख करोड़ ? बोलने के लिए तो बोल देते हैं, बोलने के लिए तो बयान बहादुर पहले हैं आप लोग, काम नहीं होगा आपसे और देश की जनता यह जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 में, कहा गया है महोदय कि अमकी के गांव में बहुरियो नहीं औरां । वर्ष 2024 में जो ये जायेंगे, इनका नामोनिशान नहीं मिलेगा । विजय सिन्हा जो माननीय नेता विरोधी दल हैं, उस लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे और कल बोल रहे थे कि हम सरकार में आयेंगे, हम जब सरकार में आयेंगे कार्रवाई करेंगे और एक संस्कार की बात कर रहे थे यह सदन है नागपुर का कैंप नहीं है, ये कहते थे कि कफन बांध लिये हैं, यह सदन है बिहार विधान सभा का और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सदन चलता है, सदन के नेता नीतीश कुमार जी हैं यहां कफन से और छप्पन से काम नहीं चलेगा । यहां अगर काम करके दिखाना है तो दिखाओ और नहीं तो जनता आपको बाहर करेगी । आप कफन बांधकर घूमते हैं, इन्होंने सदन में कहा कि हम कफन बांध लिये । अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी, एक तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे मजदूर भाई सब जगह फैले रहते हैं । पूरा विश्व जो है 3 साल तक कोरोना महामारी झेला और उस परिस्थिति में भी अपना जो साधन थे, उस साधन से सरकार ने जो व्यवस्था की, हर जोन का डिवाइडेशन किया, ग्रीन जोन, रेड जोन और जो जिस स्थिति का था वैसी जगह रखकर उनकी समुचित व्यवस्था करवाये, समुचित रख-रखाव और इलाज करवाये और यहां तक कि कोरोना से जो मरे उनके परिजनों को सहायता राशि भी दी गई । इसके लिए मैं तमाम कोरोना पीड़ित परिवारों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका 15 मिनट का समय समाप्त हो गया...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी 4 मिनट तो खा गये हैं ये लोग ।

अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है, आप बैठिये, माननीय सदस्य आप बैठिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी कानून हम सभी लोग कसम खाते, शराबबंदी कानून अगर लागू हुआ है, आज जाकर देखिये समाज में शांति है। कौन सदस्य कहते हैं अगर हम जाते थे क्षेत्र में तो डर लगता था कि कहां, कौन पीकर के अनाप-शनाप बोल देगा । आज किसी की हैसियत नहीं है कि कोई रोड पर पीकर के डगमगाता हुआ दिखायी दे । अध्यक्ष महोदय, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में भी सरकार ने जो 112 नंबर जो करवाया है कि 15-20 मिनट में गांव के किसी भी कौने में वह गाड़ी पहुंचती है वहां, उसके लिए भी सरकार ने 10459 पुलिसकर्मियों की बहाली भी की है और आगे भी करने की तैयारी भी है । कृषि के क्षेत्र में भी सर्वांगीण विकास किया गया है । अध्यक्ष महोदय, जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत भी...

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : सरकार ने सराहनीय कार्य किया है । एक चीज और मैं बताना चाहता हूं । मुख्यमंत्री आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत जिस गरीब का घर अधूरा है, जिस गरीब का घर पहले जो बना है जो जर्जर है आज सरकार उसको भी 50000 रुपये दे रही है । यह सरकार गरीब की बात करती, अल्पसंख्यक समाज के लिए भी सरकार ने 635.90 करोड़ रुपये का अलोटमेंट किया है, सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है, सारे सरकारी मदरासों में बहालियां हो रही हैं । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा, एक राहत इंदौरी साहब का शेर हमको याद आ गया तो हम लिख लिये...

अध्यक्ष : सुनाइये, सुनाइये । ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : ''अगर खिलाफ हैं, होने दो जान थोड़े ही हैं ।
ये धुआँ है कोई आसमान थोड़े ही है ।
सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में ।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है ।
जय हिंद, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार जी आपका समय 15 मिनट है ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिये । काहे कि आप लोग तो अपना वादा किये हुये चीज को...

अध्यक्ष : माननीय राजेश बाबू, आप अपना भाषण कीजिये, इधर-उधर न देखिये, आसन की तरफ देखिये और बोलिये ।

टर्न-17/मुकुल/02.03.2023

श्री राजेश कुमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम आज यहां पर अपने महागठबंधन की सरकार के समक्ष जो वित्तीय चुनौतियां हैं, मैं एक शेर के माध्यम से आगे की बात को रखना चाहता हूं । हमारी सरकार जब बनी और केन्द्र सरकार का किस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था, हमलोग जो अपेक्षा किये थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का वह आज हमारा सपना ही रह गया । इसी संदर्भ में मैं एक शेर कहना चाहता हूं, हमारी महागठबंधन की जो सरकार है उसकी तरफ से :

''हमारी राहों में बबूल बहुत है,
ऊपर से हमारे ऊपर वसूल भी बहुत है ।''

इसलिए कि हम सरकार की नीतियों की जितनी भी बुराई करें, लेकिन जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, हम अपने संसाधन से जो व्यवस्था दे रहे हैं और जनहित में जो काम कर रहे हैं, भले आज कोई कुछ कह ले, लेकिन दो-चार बात को कहकर मैं आगे की बात को आगे बढ़ना चाहूंगा कि महागठबंधन की सरकार ने वर्ष 2023 का बजट 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ का पेश किया है और यह पिछले बजट से 24 हजार 194 करोड़ ज्यादा है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केन्द्र से हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारी जी0एस0टी0 के पैसे बाकी हैं, ग्रामीण विकास पर 11 हजार कुछ करोड़ रुपया बाकी है तो हमारी महागठबंधन की सरकार जो कुछ भी कर रही है वह अपने संसाधन से कर रही है और यह सरकार जो केन्द्र की सरकार है वह तोड़ने-मरोड़ने में विश्वास रखती है, उनको अपने विकास के लिए किये गये वायदों को कभी पूरा करने की बात नहीं करते हैं । हम यहां पर पुराने बजट का पेपर लेकर आये हैं, केन्द्र सरकार का बजट और बिहार सरकार का बजट । बिहार का बजट है कि बिहार में रोजगार की बारी और केन्द्र सरकार कहती है कि अमृतकाल की उड़ान । अब यह कैसी अमृतकाल की उड़ान है कि आप बेरोजगार की बात नहीं करते और यह ऐसी उड़ान है कि पता नहीं ये कौन से जहाज से कहां उड़ान कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता । लेकिन यह उड़ने वाली सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी जनता के बीच में रहते हैं और आपको भी जनता चुनकर भेजी है, आपका भी दायित्व है लेकिन

इसका मतलब नहीं है, विपक्ष का काम है सरकार को उनकी नीतियों के बारे में उसको आईना दिखाना, यह नीति नहीं है कि सरकार को आप केवल झूठा साबित करें और उनके विकास के कार्यों को झूठलाने का काम करें । वर्ष 2023 में बिहार का विकास दर 10.34 परसेंट रही है, लेकिन हमारी महागठबंधन की सरकार के बजट का 8 सूत्री प्राथमिकता के आधार पर यह लगभग, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह काफी काबिलेतारीफ है, अध्यक्ष महोदय । ये जो युवाओं के रोजगार जो 8 सूत्री है उनमें मुख्य हैं- युवाओं के रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, कृषि और ग्रामीण विकास में वृद्धि, हरित विकास, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास अर्थात् हम भले ही राजनीति कर लें, लेकिन जिस तरह से बिहार के साथ अन्याय हुआ है और जिस तरह से बिहार सरकार, हमारी सरकार विकास की है, चाहे जल-नल योजना की, आज उसके मॉडल एस्टीमेट को केन्द्र सरकार अनुपालन करना चाह रही है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, जिस तरह से ये अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो योजनाएं हैं, ये उनका सशक्तिकरण करने का काम किये हैं । आज केन्द्र में सारी संपत्तियां प्राइवेट की जा रही हैं और उसमें किसी को रोजगार का अवसर नहीं है । चूंकि हम जानते हैं, जब यहां पर विपक्ष के लोग खड़े हैं तो आप जो प्राइवेटाइजेशन में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो आरक्षण है वह प्राइवेटाइजेशन होने से रेलवे का और सारे जगहों का, उस आरक्षण पर कुठाराघात है और साइलेंट मोड में आप रहकर उस आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं। इस पर भी बात होनी चाहिए कि आप केन्द्र में रहकर जिस तरह से हमारी योजनाओं को बंटाधार किया है उसको भी आपको देखने की आवश्यकता है । आप भले ही रोजगार के किये वायदों पर, आप अल्पसंख्यक मॉब-लिंचिंग जो करते हैं, वह मॉब-लिंचिंग यहां बिहार में नहीं चला और आदरणीय नीतीश कुमार ने इस तरह से लोगों को, समाज के लोगों को जोड़कर काम करने का काम किया है, इसलिए आपका कोई भी कुचक्र हमारे राज्य में नहीं पड़ रहा है । हम समझदारी से काम लेने वाले लोग हैं, हम समझदारी से विकास करने वाले लोग हैं, हम समझदारी से किसी समाज या वर्ग के साथ भेद-भाव करने वाले नहीं हैं । लेकिन मैं आपको एकाध चीज याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता थोड़ी देर पहले अपना वक्तव्य दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार के राजस्व स्रोत पर टिप्पणियां की हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार वर्ष 2023-24 के बजट को क्यों भूल गई है, जिसमें सबसे ज्यादा आय आयकर से आता है और सर्वाधिक ब्याज, ब्याज दर की

आमदनी से होती है । आज ब्याज दर किस पर लागू है, हम गरीब के आटा पर जी0एस0टी0 लगा दिये, हम गरीब के खाने वाले तेल पर जी0एस0टी0 लगा दिए और आप गरीब जनता का खून चूसकर अपनी आय के स्रोत का संसाधन बना रहे हैं । आपको आय को जहां पर विकसित करना चाहिए, चाहे वह अडानी हो, चाहे वह अम्बानी हो उनको आप कर्ज अरबों-अरबों देते हैं और उसको नन-परफोर्मिंग एसेट कहकर उसको अनुदान में माफ कर देते हैं और गरीबों का जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको पचास बार बैंकर्स के साथ बैठकर आप दिये गये अनुदान को वसूली करने का काम करते हैं । इसलिए मेरी ज्यादातर टिप्पणियां यह है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, माननीय प्रतिपक्ष महोदय को मैं अनुरोधपूर्वक कहना चाहता हूं कि आप यू0पी0ए0 सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार को देखिए और अपनी सरकार को देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए और एक दिन उस पर भी डिबेट कर लीजिए कि जब हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हमारा राज्यांश मात्र 15 परसेंट था, लेकिन आज हमारा राज्यांश 60/40 है, हमारे गरीब राज्य के साथ आपने अन्याय किया है इस पर भी बात कीजिए । आपने जितनी छाती ऊंची करके जिस तरह से कहा बोलिए मैं एक लाख दे दूं कि 70 हजार दे दूं और आपने दिया कुछ नहीं । आज तक हमलोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार जब हम बिहार राज्य में हैं और हम केन्द्र से अच्छी अपेक्षाएं रखते हैं तो वह कुछ नहीं हैं । आज ग्रामीण विकास में जिस तरह से मनरेगा का हास्य उड़ाया गया था लोकसभा में, आज वही मनरेगा कोरोना काल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और हमारे नेता राहुल गांधी के अनुदेश से इतना अच्छा काम किया कि बिहार में कोरोना का प्रकोप घटा। हम कम संसाधन, उस समय लोगों में जितनी पीड़ा थी, चाहे ऑक्सीजन का या कुछ का, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे औरंगाबाद जिला का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं था लेकिन तत्काल हमलोगों को सासाराम से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया गया है, यही है महागठबंधन की सरकार की नीतियों की चर्चा । अंत में मैं यह बता देना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं आटा पर जो जी0एस0टी0 बढ़ा उस पर चर्चा करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उज्ज्वला गैस के बारे में चर्चा करते हैं, आप तो कहे थे कि हमारी माता, बहनें जिस तरह से मुंह से चूल्हा जलाकर के, गोइठा का कांडा जलाकर के, लकड़ी पर हमारी माताओं एवं बहनों की आंखें लाल हो जाती है, हमारी बहनें दम्मा पेसेंट हो जाती हैं । आज उज्ज्वला योजना की कौन सी स्थिति है, इसके बारे में आप ही हमें बता दें हम उसको मानने के लिए तैयार हैं और मेरी चुनौती है कि

आज 80 परसेंट हमारी माताएं एवं बहनें उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस में एल0पी0जी0 भराने में असक्षम हैं । आज हमारी सरकार स्वयं सहायता समूह से और अन्य कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण की ओर काम कर रही है

क्रमशः

टर्न-18/यानपति/02.03.2023

(क्रमशः)

श्री राजेश कुमारः और यदि 5 परसेंट से 10 परसेंट यदि उज्ज्वला योजना में कोई गैस सिलेंडर रिफीलिंग करवा रही है तो वह है सीधे तौर पर महागठबंधन की सरकार की नीतियों के कारण हो रही है वरना आपने तो सारा खत्म कर दिया । आज जो है कल से परसों तक गैस सिलेंडर का दाम आप देख लीजिए, आसमान छू गया, आज जब जो है जो 270 रुपये गैस सिलेंडर था तो आप रोड पर थे । हम सारे विपक्ष के नेता को सादर आमंत्रित करना चाहते हैं कि 15 सौ रुपये, साढ़े 15 सौ रुपये गैस सिलेंडर, एल0पी0जी0 हो गया है, आइये हम सब मिलकर के आंदोलन करें कि हम गैस सिलेंडर का दाम कम करिये और जब यदि यह नहीं है तो इसका मतलब आप जनता के दायित्वों से मुंह मोड़ रहे हैं, आप जनता के हित के लिए आप केवल राजनीति कर रहे हैं । इसलिए मैं सदन के माध्यम से आपको आग्रह करना चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी का जो है केंद्रीय मंत्री महिला थीं मैं उनका नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं कि एक समय था कि आप जब एल0पी0जी0 का दाम 270 रुपया था यू0पी0ए0 सरकार में तो रोड पर रात दिन बैठे रहते थे और उस समय के प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजते थे । आज आप कहां हैं कि 15 साढ़े 15 सौ एल0पी0जी0 गैस का दाम बढ़ गया और आप जो है चूड़ी अपने हाथ में पहनने की बजाय आप अपने किसी नेता को देने का काम कीजिए इसलिए मैं सच बात को कहना चाहता हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं यदि इस बात पर कोई शंका है तो आप बैठकर के हमसे बात कर लीजिए, हमारे सारे विधायकों से बात कर लीजिए लेकिन हम अभी एक बजट पढ़ रहे थे जिसमें संपर्कता पथ में हमारी बिहार सरकार ने 12 हजार 300 करोड़ रुपये का दिया है लेकिन आश्चर्य देखिए जिस तरह से झिलमिल-झिलमिल जो है डाउट में रह कर के वह सड़क बनाने का जो बजट में प्रावधान किया है कि 2000 से 72 लाख कि0मी0 हम बनाये हैं आज तीन साल हो गए, तीन साल में यह कहते हैं कि 72 हजार कि0मी0 बना है और हमारी सरकार एक साल में 12 हजार 371 करोड़ का काम कर रही है इसपर जो है हमारी सरकार स्पष्टता से काम कर रही है और आप जो है सारा ब्लैक डॉट में काम कर रहे हैं, यह हमारी ट्रांसपेरेंसी की सरकार है । इसी

तरह से मनरेगा के बजट में 2024 में मात्र 48 दिन का कार्यदिवस दिया गया है हम सौ दिन के जब यू0पी0ए0 की सरकार थी और हमारे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी यू0पी0ए0 की अध्यक्षा थीं तो उस समय मनरेगा में हम सौ दिन की गारंटी देते थे । आज क्या हो गया, आपको भी संघर्ष करने की जरूरत है और माननीय प्रधानमंत्री से, केंद्र से आप बहुत ही विशाल जनसमर्थन से जीतकर आए हैं तो जनता के साथ आप अन्याय नहीं करें आप 48 दिन ही कार्यअवधि के बजाय आप इसको सौ दिन करा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही राजनीति करने वाले लोग हैं । इसलिए मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप जब हमारी सरकार का गठन हो रहा था, आप जो है उस तरफ थे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बड़ा.....

(व्यवधान)

जोड़ दीजिए न, जोड़ दीजिए । उस समय थे तो बड़ा अच्छे लग रहे थे। आप जब सरकार में थे और श्री नीतीश कुमार जी और इनको समर्थन दे रहे थे तो नीतीश कुमार जी तो बड़ा अच्छा लगते थे । अब इनको पता नहीं क्या हो गया कि साथ-साथ मिलकर के हमलोग जब गठबंधन बनाए तो आपको जो है नीतीश कुमार जी की नजर उतारनी चाहिए उनको कि हमलोग जो है गठबंधन की सरकार नजर उतारेंगे उनकी कि आपकी नजर न लगे, नहीं तो हमारा जो है मध्य प्रदेश की सरकार को नजर लग गई, हमारा जो है गोवा की सरकार को नजर लग गई इसलिए हमलोग जो है नीतीश कुमार जी को नजर से बचाएंगे यह हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं और 2024 में.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री राजेश कुमार: देश में क्या होगा वह तो आप देख लीजिएगा लेकिन बिहार में आप नहीं सिमट गए तो आप जो कहिएगा सो होगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री राजेश कुमार: बस, आधा सेकंड सर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा मौलिक अधिकार दिया आज जो है केंद्र की सरकार हमारा मौलिक अधिकार भी छिनने का डर है । हमारे बोलने की अभिव्यक्ति भी खत्म कर रही है । हमारी आजादी जो है कंस्टीट्यूशन से लेकर के जितने भी कंस्टीट्यूशन जो निष्पक्ष नहीं हैं उसको जो है हमलोग को हमला करने का काम कर रही है ।

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री राजेश कुमार: मैं इसी के साथ आप सब का, अध्यक्ष महोदय का, पूरे सदन का आभारी और विपक्ष का भी आभारी कि आपने हमारी बात को सुना उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डॉ0 संजीव कुमार अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट ।

डॉ0 संजीव कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, माननीय मुख्य सचेतक महोदय मुझे जो बोलने का मौका दिया गया है आज मैं बताना चाहता हूं बिहार का बजट जो था जस्ट ए कंपरीजन है कि 2004-05 में 23 हजार करोड़ का बिहार का बजट था और आज 2 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का बजट है और वह भी यह बजट कब है, आप देख सकते हैं 12 गुना बजट बढ़ गया पिछले 17 साल में और वह बजट कब है जब केंद्र सरकार एक परसेंट भी अपना अतिरिक्त सहयोग नहीं की अपने बलबूते पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की दशा और दिशा को बदल दिया इस 17 साल में । दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरू से हमारी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे दल के सारे लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दें, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार में भी उद्योग लगते और यह बजट जो 2 लाख 61 हजार करोड़ का है यह बजट बढ़कर के 5 लाख करोड़ का होता लेकिन यह जो हमारी केंद्र में भाजपा की सरकार है वह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यह आज से नहीं, यह ठग रही है कि जब 9 साल से वहां केंद्र में सरकार है तो क्या दायित्व बनता था, सबकुछ गुजरात में ही क्यों होता है बिहार में क्यों नहीं होता है आज मैं अपने भाजपा के साथियों से कहता हूं, आपलोग के तो प्रगाढ़ संबंध हैं अडानी और अंबानी से क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल बनाकर जाते हैं, हाथ पकड़ कर, पैर पकड़ कर कहते हैं बिहार में भी कुछ इंवेस्ट कीजिए, अकेले कितना पार्टी चलवाइयेगा बिहार के विकास में भी कुछ रोजगार बढ़ेगा अगर वे लोग यहां पर आएं । यह नहीं करेंगे इनको भी बिहार से कोई मतलब नहीं है इनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है, जाति में हर लोगों को डिवाइड कर के डिवाइड ऐंड रूल वाली रणनीति अपनाए हुए हैं । सबसे बड़ी बात मेडिकल का मैं हूं मैं बताता हूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, पहले बिहार में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज के दिन में 17 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गए हैं और वह भी अपने बल पर 17 मेडिकल कॉलेज खुले हैं । 12 और स्ट्रीम लाइन है अगले दो साल में 12 मेडिकल कॉलेजेज और खुल जाएंगे, 30 मेडिकल कॉलेजेज हो जाएंगे । हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, 33 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है आगे भी खुलने वाला है । रोजगार के क्षेत्र में देखिए आपलोग तो दो

करोड़ की बात करके जनता को ठग लिए दो करोड़ रोजगार देंगे हर साल । और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी बोले और चार लाख रोजगार जो नियुक्ति है, सरकारी नौकरी इसी साल देनेवाले हैं और उसमें डिपेंडेंट रोजगार अलग से व्यवस्था होगा लोगों का, 10 लाख की जो बात है वह भी हमलोग कर रहे हैं तो हर तरह से हमलोग लगे हुए हैं और जो नीति माननीय मुख्यमंत्री जी अपनाते हैं वही नीति केंद्र सरकार अपनाती है बाद में उसका अनुकरण करती है । जैसे कि हर घर नल जल योजना बिहार में 2016 में शुरू हुआ और केंद्र सरकार जल-जीवन मिशन के नाम पर अगस्त 2019 में शुरू किए उसको । जीविका बिहार में अक्टूबर 2007 से शुरू है और आज के दिन में एक-सवा करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं, केंद्र सरकार उसी का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन 2011 लाई । हर घर बिजली 2016 में शुरू हुआ और केंद्र सरकार सौभाग्य योजना के नाम से 2017 में किए । तो जो-जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जल-जीवन-हरियाली जो है बिहार में अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया तो केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना के नाम से 2022 में उसको लाए । तो इतना कुछ आपलोग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दें और इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन होना चाहिए बिहार में ।

(क्रमशः)

टर्न-19/अंजली/02.03.2023

डॉ0 संजीव कुमार (क्रमशः) : इसके लिए मैं चाहता हूं कि बिहार में एक आंदोलन होना चाहिए जब और बजट बढ़ेगा, आज आप देख रहे हैं कितना दुखद है, सारे बिहारी दुखी हैं कि तमिलनाडु में बिहारी की हत्या हो गई, जड़ में जाइए, क्यों हत्या हुई ? आप लोग यहां पर दो साल मात्र सरकार में नहीं थे, 15 साल लगभग सरकार में थे तो क्यों नहीं उस वक्त आपलोग, जब केंद्र में भी सरकार में थी तो विशेष राज्य का दर्जा दिए, उस वक्त कहां थे ? इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं । अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता और आज जो भी उद्योग बिहार में लग रहे हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कृपा से लग रहे हैं और इनकी सोच है, दूरदर्शिता है कि आज बिहार में उद्योग भी लग रहे हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है और आप आज इथेनॉल प्लांट की जो बात कह रहे थे कि आपके शासनकाल में लगा तो मैं थोड़ी बात में आपको बताना चाहता हूं कि इथेनॉल बनाने का परमिशन माननीय मुख्यमंत्री 2006-07 में ही केंद्र सरकार से मांग लिए थे, उस वक्त उसमें भी नहीं मिला, भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद भी नहीं मिला तो शुरू से ही ये इसमें लगे

हुए थे अगर ये होते तो पहले से ही इथेनॉल प्लांट आज बिहार में लग जाता । आज महिला सशक्तिकरण की बात देखिए, आज हजारों शिक्षकों का, डेढ़ लाख शिक्षकों का रोजगार इसी साल इसी में बहाली होने वाली है स्वास्थ्य विभाग में...

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, केंद्र में किसकी सरकार थी...

डॉ0 संजीव कुमार : कल तक आप क्यों चुप थे, आप तो साथ ही में थे 15 साल, ढोल बजा रहे थे 15 साल और दो दिन में आपको परेशानी हो गई ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक बाबू आप स्थान ग्रहण करें । आप बोलिए ।

डॉ0 संजीव कुमार : इनलोगों को सच्चाई बर्दास्त नहीं होती है । महोदय, विशेष राज्य का दर्जा में सब चुप बैठे हैं, आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं ? मैं बात कर रहा हूं उसके बाद हर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गये, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुल गये, हर जिले में आई0टी0आई0 कॉलेज खुल गये, यह किनकी देन है, सड़कों का जाल बिछ गया, हर घर नल-जल योजना के बारे में जो कह रहे थे कि कितना परसेंट है, मेरे विधान सभा में 90 परसेंट कार्यरत है और हरेक विधान सभा में है, बस दस परसेंट जो होता है वीयर एंड टीयर चलता रहता है, मैकेनिकल फॉल्ट उसको आप लोग उजागर करते हैं । लेकिन जो 90 परसेंट कार्यरत हैं उसकी बात आप लोग नहीं करते हैं । मैं अमेरिका गया था, वहां पर बिहार-झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने मुझे संगठन में बुलाया था तो वे इतना खुश थे जो दस साल बाद बिहार आए तो बिहार की दशा और दिशा को बदलता हुआ देखकर वहां पर भी लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और पहले लोग रिटायर करते थे, कहीं पर नौकरी करते थे, वहीं पर घर बना लेते थे आप लोग खुद बताइए, आज गांव में जाकर देखिए कोई भी जवान अगर झारखंड में हो चाहे छत्तीसगढ़ में भी नौकरी किया हो, रिटायरमेंट के बाद आकर अपने गांव में घर बना रहा है चूंकि गांव में आधारभूत संरचना हो गई है, बिजली है, पानी है, सड़क है, कानून व्यवस्था अच्छी है और अपने गांव में वापस आ रहे हैं इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग भी सहयोग करें, अगर आप लोग सहयोग करेंगे, केंद्र में सरकार है तो जरूर हमारा बिहार, जिसको आप लोग हर समय और आप लोग बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं पूरे देश में जबकि ऐसा कुछ नहीं है । हमारे बिहार का जो इतिहास है गौरवान्वित इतिहास है उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस इतिहास के गौरव को और बढ़ावा दिया जा रहा है । हमारा बिहार जो है वह गौतम बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है इसलिए आप लोग बिहार को बदनाम जंगल

राज के नाम से नहीं किया करें, ऐसा कुछ नहीं है । छह महीने पहले मंगल राज और आज जंगल राज की बात आप लोग करते हैं वही राज है, वही मुख्यमंत्री हैं, वही कानून व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है । हर जगह जो भी घटनाएं, लोग बालू के कारोबारी की बात कहते हैं जांच का विषय है । महोदय, मैक्सिमम बालू के कारोबारी भाजपा के सदस्य निकलेंगे, उनकी जांच कराई जाय । सक्रिय सदस्य भाजपा के निकलेंगे बिहार में जितने बालू के कारोबारी हैं तो खुद से कुछ बोल रहे हैं तो वह अलग बात है । माननीय मुख्यमंत्रीजी से हम यही आग्रह करते हैं कि हर जगह मेडिकल कॉलेज बन गया, खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, यही मेरा आग्रह है विशेष और कुछ नहीं कहना है और भाजपा के लोग भारत माता की जय बोल कर के लोगों को गुमराह करते हैं कि भाई भारत माता की जय क्यों, बिहार की जय क्यों नहीं करते हैं आप । बिहार की जय बोलिए । बिहार भी भारत का अंग है, बिहार को जय बोलिएगा तो भारत माता की जय स्वयं होगी । आप लोग अडानी से निकलिए, अडानी के कब्जे से निकलिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए ।

डॉ0 संजीव कुमार : बिहार की जय बोलिए, भारत माता की जय के साथ बिहार की भी जय बोलिए सिर्फ भारत माता की नहीं, जय बिहार बोलिए । इसमें क्यों कष्ट हो रहा है?

(व्यवधान)

रामचरित मानस की तो बात है ही । हिंदुत्व का ठेकेदार आप ही लोग हैं क्या ? मतलब जो आपके दल में नहीं हैं वे हिंदु नहीं हैं, वे राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं क्या ? ऐसा नियम बना दिए हैं आप लोग । रामचरित मानस के बारे में सिर्फ आप ही बोलिएगा और कोई नहीं बोलेगा ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

हर दल के लोगों को अधिकार है अपने धर्म के बारे में बोलने का, सिर्फ आपको नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लें । भारत में आप लोग 370 हटा सकते हैं लेकिन प्रावधान को बदलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में आप लोगों को दिक्कत है । 370 हटाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह प्रावधान बदलिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, यह अच्छी बात होगी । धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अजीत कुमार सिंह ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट पर चर्चा चल रही है, वाद-विवाद में बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी सत्र का आज चौथा दिन है और चार दिनों से मैं जो प्रतिपक्ष की बेचैनी देख रहा हूं, उनके चेहरे पर अभी हाल ही में सत्ता जाने का जो दुख है वह स्पष्ट झलक रही है और इसी में वे कई बार अपने लफ्जों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कई बार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किए, जिससे बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन को भी शर्मिंदा होना पड़ा, खैर यह उनका दुख है यह वे समझें । महोदय, अभी छह महीने पहले सरकार बदली है, पहले जो लोग इधर थे अभी उधर हैं, हमलोग उधर थे, उधर से इधर आए हैं। भाषा भी ऐसे ही बदलती रहती है । यह राजनीति की खूबसूरती भी हो सकती है या उसकी सच्चाई भी हो सकती है ।

(व्यवधान)

हां, वह तो मालूम है, वही तो बता रहे हैं । महोदय, लेकिन जो हकीकत है उस पर बात करना जरूरी है । निश्चित तौर पर इस बार का जो बिहार का बजट है उसकी तारीफ की जानी चाहिए । तारीफ करने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जैसे बजट ने खुलकर रोजगार के बारे में बात किया है । इतने दिनों से हम बजट देख रहे हैं, केंद्र का बजट भी हमने हाल ही में देखा, किसी बजट ने नौकरियों की बात नहीं की, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें दस लाख नौकरी देने का संकल्प उन्होंने स्पष्ट तौर पर दुहराया, यह पिछले दोनों बजटों में नहीं दिखाई दिया । इसके लिए बिहार के नौजवानों की तरफ से मैं इस बजट का तारीफ करता हूं । लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार के नौजवानों में खुशी का माहौल है कि उनको अब नौकरी मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों दो करोड़ नौकरी का झांसा देने वालों ने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है । हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो बजट में वादा किया है उस वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे और बिहार के नौजवनों की जो चिर-लंबित मांग और प्रतीक्षा है उसको जरूर आने वाले समय में बिहार की सरकार पूरा करेगी और दस लाख नौजवानों को जरूर बिहार की सरकार सरकारी नौकरी देगी । महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है कृषि का बहुत बड़ा योगदान है जी0डी0पी0 में भी कृषि की भूमिका हमेशा ही अति महत्वपूर्ण होती है लेकिन इस बजट में हमने देखा महोदय, जब हमलोग बात कह रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब यह भी है कि हम अपने ही बजट को समृद्ध भी करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यही बजट आने वाले दिनों में बिहार की जनता के दिशा और

दशा को बदलेगा इसलिए हम बजट को समृद्ध करना चाहते हैं । हमको जो समझ में आ रहा है । (क्रमशः)

टर्न-20/सत्येन्द्र/02-03-2023

श्री अजीत कुमार सिंहः (क्रमशः) क्योंकि हम जानते हैं कि यही बजट आने वाले दिनों में बिहार के जनता की दिशा और दशा को बदलेगा इसलिए हम बजट को समृद्ध करना चाहते हैं । हमको जो समझ में आ रहा है, उससे हम सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं और बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि अगर बिहार के विकास का सपना हम देखते हैं तो उसके लिए कृषि के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका में रखना होगा । बिना कृषि का विकास किये बिना किसानों के आय को बढ़ाये, बिहार के विकास की कोई भी कल्पना नहीं हो सकती । अब मैं उनकी तारीफ तो करूंगा नहीं, जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे और अभी तक उन्होंने किसी भी चीज का दाम नहीं बढ़ाया, किसानों का आय दुगुना नहीं किया इसलिए किसानों के बारे में बिहार की सरकार को विशेष चिन्ता करने की जरूरत है। महोदय, इस बजट में किसानों के लिए कृषि के लिए 2 हजार 782 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है जो महज इस बजट का 2.8 प्रतिशत है । बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बजट का प्रावधान है और इससे जो हम किसानों के डेवलपमेंट का सपना देखते हैं, विकास का सपना देखते हैं वह नहीं हो पायेगा। महोदय, बिहार के किसानों की चिर लंबित मांग है, जिसको केन्द्र की सरकार नहीं पूरा करना चाहती है जिसके खिलाफ किसानों ने दिल्ली में एक बहुत ऐतिहासक आंदोलन को अंजाम दिया, तब 56 ईंच की छाती को पीछे हटना पड़ा महोदय, बिहार अगर देश के केन्द्र में आना चाहता है तो बिहार से मौजूदा शक्ति को उखाड़कर फेंकना है इसके लिए बिहार के किसानों के हित में बिहार की सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करना होगा और मंडी व्यवस्था को सम्पूर्ण तरीके से लागू करना होगा महोदय । महोदय, हमारी लड़ाई इस देश के ऐसे लोगों से है जो देश की सम्पूर्ण सत्ता पर उसने बर्चस्व कायम कर लिया है जिसने पूंजी और कॉरपोरेट के गठजोड़ के माध्यम से, अंबानी और अडाणी से मिलकर लोकतंत्र के तमाम संसाधनों को अपने चंगुल में ले लिया है महोदय । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हुए इस बात को कहते हैं कि मीडिया के कुछ लोग हमारी भी बात को तरजीह दे । इस देश के 75साल के लोकतंत्र पर तरस आता है कि एक मुख्यमंत्री की बात इस देश का अखबार नहीं छापता, वह उन्हीं की बात छापता है जिनसे वह पैसा खाता है, पेड न्यूज लिखता है । महोदय, बिहार में जब तक नहरों

का आधुनिकीकरण नहीं होगा, मधुबन जलाशय योजना का निर्माण नहीं होगा और महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां पर एक परियोजना है मलई बराज योजना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में भी उस सवाल को उठाया था । महोदय, वर्ष 1980 से यह योजना चल रही है । सरकार आती गयी, उधर के लोग इधर और इधर के लोग उधर आये-गये लेकिन अभी तक वह योजना पूरी नहीं हुई है । महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उस योजना के पूरा होने से वह पूरा इलाका जो है सिंचिंत होगा और महोदय, मुझे अपनी सरकार से बहुत उम्मीद है इसलिए मैं उम्मीदों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूँ , पहले मैंने यह बात नहीं कहीं थी जब वे लोग सत्ता में थे लेकिन आज मुझे यह कहने की हिम्मत है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार, हमारी इन मांगों को जरूर पूरा करेगी । महोदय, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कई मेडिकल कॉलेज की स्थापना बिहार के अंदर किया और सौभाग्य से मैं जिस जिला से आता हूँ, जिस विधान-सभा का नेतृत्व करता हूँ हमारे क्षेत्र में भी आप एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आप खोल रहे हैं इसके लिए तहेदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहां ऐसे ऐसे अस्पताल और भी खुलेंगे । महोदय, समाधान यात्रा में हमारे यहां माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, निश्चित तौर पर ये बहुत काबिलेतारीफ यात्रा रही है । कई सारी समस्याओं को हमने उनके सामने लाया और उसको उन्होंने उस पर बहुत ही विस्तार से बातचीत किया और बहुत खुशी की बात है कि एक सवाल जो हमलोगों ने उठाया था कि डुमरांव में उस्ताद विस्मिला खां साहब के नाम पर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाय तो महोदय, आपको यह जानकार के खुशी होगी कि सरकार के तरफ से उस दिशा में प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के लिए भी मैं सरकार को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, बजट में बहुत सारी चर्चाए हैं, योजना के मामले में 1 लाख करोड़ रू0 का हमारा बजट है महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बजट को और भी बढ़ाने की जरूरत है, पिछला बार भी बजट इतना ही था और अभी कई सारी योजनाओं को पूरा करने की जरूरत है महोदय । महोदय, पूरे बिहार में अभी जो चर्चा बिजली पर चल रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गरीबों की बिजली बिल नहीं जमा करने के कारण काट दिया जा रहा है और ये घटनाएं लगातार बिहार में घट रही है और पूछने पर अधिकारी लोग कह रहे हैं कि ऊपर से कहा जा रहा है,एम0डी0 का फोन आया था इसलिए बिजली काट दी गयी है, वहीं कुछ लोग का कितना भी बिजली बिल बकाया हो लेकिन उनकी बिजली नहीं काटे जा रहे हैं। इसके

सही इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी समस्या है, महोदय इसको ठीक करने की जरूरत है । बाकी बिजली बिल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कृषि में मात्र 70 पैसा, 75 पैसा प्रति यूनिट बिजली बिल लिया जाता है लेकिन महोदय घर में जो बिजली जलाया जाता है, उसको जो रेट है वह बहुत ज्यादा है 8 रू0 प्रति यूनिट बिजली हमारे गरीबों को देना पड़ता है महोदय, इसलिए इस बजट के माध्यम से आपसे मांग करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार में जिस तरीके से, दिल्ली मतलब आपकी सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी वाली सरकार जिस तरह से 200 यूनिट बिजली माफ किया है, हमारी सरकार को भी गरीबों के लिए इस तरह से बिजली माफ करने का कोई प्रावधान बिहार की सरकार को लाना चाहिए और गरीबों को इसका लाभ देना चाहिए । महोदय, बहुत थोड़ा सा चूंकि बहुत सारी चर्चाएं हुई, केन्द्र के बारे में, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां हैं भी नहीं और इधर संख्या भी कुछ कम हो गयी है, बहुत सारी बात है । अभी हाल ही में महोदय केन्द्र सरकार का बजट पास हुआ, वे कह रहे थे कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं, हमने कहा कि धूल तो आपके चेहरे पर है और आप आईना क्यों साफ कर रहे हैं, आप किसको आईना दिखा रहे हैं, आईना तो आपको देखने की जरूरत है । महोदय, इन्होंने मनरेगा में बजट को कम कर दिया है । महोदय, 2020-21 में मनरेगा का बजट 98 हजार 467 करोड़ रू0 था जो 2021-22 में 79 हजार 400 करोड़ रू0 हो गया और इस बार मात्र 60 हजार करोड़ रू0 हो गया । महोदय, यहां तक कि काम का दिन भी नहीं बढ़ाया गया और लगातार मनरेगा में कटौती किया जा रहा है जबकि ये लोग लगातार मनरेगा की बात कर रहे हैं । महोदय, मनरेगा के बजट में कटौती करने वालों के पास यह अधिकार नहीं है कि वे मजदूरों के बारे में बात कर सकें। महोदय केन्द्र की सरकार ने सिंचाई योजना के बजट में भी भारी कटौती की है, पहले 12 हजार 954 करोड़ रू0 इसके लिए आवंटित था लेकिन इस बार उन्होंने घटनाकर 10 हजार 787 करोड़ रू0 कर दिया। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इन्होंने भारी कटौती किया है 87 हजार 160 करोड़ से घटाकर 36 हजार 785 करोड़ कर दिया और महोदय इनके बिहार के एक सांसद हैं, बहुत बोलते हैं पिछले दिनों बेगुसराय में दो लड़कों की लड़ाई को दंगा में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहे थे । उन्होंने बिहार के मजदूरों को धमकी दिया,बिहार के मजदूरों को धमकी देते हुए कहा कि मनरेगा का पैसा नहीं देंगे, श्रम आनी चाहिए उनको जो मजदूरों के खिलाफ इस तरह की बयानवाजी करते हैं और मजदूरों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं । महोदय, देश में आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है और देश में लोकतंत्र खतरे में है, आज

ये बातें स्पष्ट तौर पर दिख रही है । महोदय, आज पूरा बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी रहा है, पूरा बिहार जिस लोकतंत्र को स्थापित किया है ,यहां पर किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हमलोग बिहार में नहीं रहने देंगे, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी महोदय । महोदय, छोटी सी बात है लाईट आपका जल गया है और हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द कहेंगे कि अब बात को खत्म कीजिये इसलिए एक छोटी सी कविता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । ऐसे ही कल कुछ हुआ, कुछ घटनाएं घटी, इधर की बात उधर हुई तो मेरे मन में यह आ गया, इसको मैंने कल ही अपने पूर्जी पर लिखा था, कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो मुझे लगा कि आज मिलेगा तो जरूर आपको सुनाने की कोशिश करूंगा । महोदय, विपक्ष के लोगों से कहना है कि कृपया हल्ला नहीं करें, ध्यान से सुनियेगा तो बाहर बयान देने में बड़ा मजा आयेगा, जैसे कल महबूब जी पर दे रहे थे तो ध्यान से सुनिये –

राष्ट्रपिता के हत्यारे को, सुबह सुबह आरती दिखाने वालों,
अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों,

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मानना है जो हत्यारे होंगे, उनको बुरा लगेगा ।

महोदय, राष्ट्रपिता के हत्यारे को, सुबह सुबह आरती दिखाने वालों,
अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों,

महोदय बोलने का मौका दिया जाय। (व्यवधान) कविता कम्प्लीट करने दीजिये ।

सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलमावा में मरवाने वालों,
और अर्द्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों,
सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों,
एलिजावेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों,
अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनके उठकर क्यों चले जाते हो।

धन्यवाद।

टर्न–21/मधुप/02.03.2023

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति । बैठ जाइये । आप लोग बैठिए । शांति–शांति । बोलिये सुर्यकान्त जी।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

(व्यवधान)

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो विकास बिहार का हुआ है, वह काबिले तारीफ है ।

उपाध्यक्ष : बीच में टोकाटोकी मत कीजिए । बैठिए ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : हर क्षेत्र में विकास हुआ है चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर आगे बढ़ा है । महोदय, इन लोगों को सोचना चाहिए, ये विपक्ष के लोग भी बिहार के ही वासी हैं, आज देश का विकास होगा क्या उसमें बिहार नहीं है ? बिहार का विकास होगा तो इन लोगों का विकास नहीं होगा ? हमारे साथी ने सच बोला तो ये लोग हल्ला करने लगे । संजय भाई को तो शुरू से हल्ला करने की आदत है ही, शुरू से ही हल्ला करते हैं । महोदय, ये लोग सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का काम किये, इनकी सरकार इनकी पार्टी, अगर हमलोग बोलते हैं तो इन लोगों को कष्ट होता है। महोदय, आरक्षण विरोधी ये लोग हैं । हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर ने आरक्षण की बात की है, उन्होंने जब आरक्षरण की बात की और उनका नाम लेने पर भी ये लोग गुरेज, परहेज करते हैं । सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने वाले लोग आज इस सदन के अंदर हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं । क्या इनके साथ अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं ? हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा अधिकार है आरक्षण लेने का, ये निजी क्षेत्र में जो तमाम हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को दे रहे हैं, हम मॉग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दें । तब हम समझेंगे कि आप आरक्षण की बात करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर आपने एक दलित को राष्ट्रपति बनाये हैं । आप इसकी बात कीजिए ।

महोदय, हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, उन्होंने कहा था कि बिहार के किसी भी कोने से आने में राज्य में मात्र 5 घंटे का समय लगेगा चाहे वह कटिहार हो, चाहे इधर सीवान हो । आज रोड चकाचक है, हर रोड चकाचक है । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है और महागठबंधन की देन है । आप लोग हल्ला मत कीजिए । आप कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी राशि देते हैं, वह हमारा टैक्स का पैसा है, हर टैक्स का पैसा माननीय प्रधानमंत्री के यहॉ जाता है, वही पैसा आप लोगों को वापस करना चाहिए तो आप वापस नहीं करते हैं और माननीय सदस्य महोदय आपलोग

हल्ला करते हैं । कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो ।

उपाध्यक्ष : अब आपका समय हो गया सुर्यकान्त जी । समय हो गया है ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलने के लिए आपने समय दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बजट भाषण पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी जी एवं डॉ0 संतोष कुमार सुमन जी को भी धन्यवाद देती हूँ । मैं गर्व से इसलिए भी खड़ी हुई हूँ कि मैं उस राज्य की विधायिका हूँ जिस राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं । मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं की देन है जो हमें यहाँ तक लाकर इस मुकाम पर पहुँचाया है ।

आप सबकी बात मैं बहुत गहराई से सुन रही थी, मुझे बहुत ही ग्लानि हो रही थी कि जनता किस उद्देश्य से हमको यहाँ पर भेजती है, जैसे लग रहा है हाउस में कि पहला क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं । बहुत दुख की बात है । हमलोग एक पॉलिसी बनाने के लिए आये हैं, हमलोग कानून बनाने के लिए आये हैं, हमलोग एक अच्छे निर्माता के रूप में हैं लेकिन इसी प्रकार से हल्ला-गुल्ला में जो देखते होंगे हमारे लोग जिन्होंने हमें नेतृत्व करने के लिए भेजा है लाखों-लाख की संख्या में, उन्हें जरूर हमलोगों के उपर गाली ही आती होगी ।

आज जो बजट भाषण के पक्ष में सभी लोग बोल रहे हैं, मैं मानती हूँ कि जो बजट भाषण बना है और जो बजट भाषण में सभी बारीकियों को देखा गया है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देती हूँ । हर वर्ग एवं समुदाय को उन्होंने नजर में रखते हुए विकास की बात उसमें पिरो दिया है । लोग किताबों में ही बात करते हैं परंतु इन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया है। जैसे महिला उद्यमी योजना- महिलाओं को कौन पूछता था लेकिन महिला उद्यमी योजना के तहत इन्होंने गॉव, कसबों, सुदूर इलाकों, पहाड़, जंगल से महिलाओं को जोड़कर इन्होंने उद्यमी योजना से जोड़ा है और इतना ही नहीं जीविका दीदीयों की लाखों-लाख की संख्या में एक बहुत बड़ा संगठन निर्माण किया । आज आप उन महिलाओं के बीच जायेंगे तो उन महिलाओं की जो दर्द सुनेंगे जहाँ से वे उठी थीं, आज उनकी तरक्की जो हुई है, वे जो बयां करती हैं, आपका रूह कॉप जायेगा कि कहीं ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला कि हमें यहाँ तक पहुँचाया ।

आज माननीय श्री नीतीश कुमार जी को सभी लोग यही कहते हैं कि 2024-2024 । 2024 में हम चैलेन्ज के साथ कहते हैं कि बिहार की सभी महिलाएँ नीतीश कुमार को हमलोग वोट करेंगे और भारी बहुमत से वे जीतेंगे । किस क्षेत्र को आप देखना चाहते हैं ? किसी क्षेत्र को आप देखिये, चाहे तो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, बिजली हो, रोजगार से संबंधित हो । अपना कृषि प्रधान देश है, केवल किताबों में दिखता था कि कृषि प्रधान देश है लेकिन इसको चरितार्थ करने के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप बनाकर इसे जमीन पर उतारने का काम किया है । फिर भी लोग कहते हैं कि काम नहीं करते हैं, काम नहीं हुआ है । आप अच्छी नजर से देखेंगे तो अच्छा काम दिखेगा, बुरी नजर से देखेंगे तो बुरा काम ही दिखेगा । इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को जितनी बार भी धन्यवाद दूँ, बहुत कम होगा । पेयजल की समस्या थी, कितना काम गिनायें । उन्होंने काम के साथ समाज की अच्छी दशा-दिशा सुधारने के लिए नई-नई योजनाओं को उन्होंने परोसने का काम किया जैसे बाल विवाह की समस्या हो, दहेज प्रथा हो, शराबबंदी हो, इत्यादि अनेक नई-नई बातें उन्होंने समाज को देने का काम किया ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : अगर समाज उसको अपना नहीं रहा है तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, हम-आपका दोष है । इतनी सारी योजनाएँ हमलोगों के बीच चल रही है तो हमलोग यही चाहेंगे, हमलोग यही कहेंगे और समाज भी यही कहेगा...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती ज्योति देवी : समाज ने आपको नेतृत्वकर्त्ता के रूप में चुनकर भेजा था, आपके क्षेत्र में इतनी सारी योजनाओं के चलने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं हम-आप सब दोषी हैं क्योंकि सभी तरह का मालिक जनता ने आपको बनाया है । आपने देखा होगा कि जब नये भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया था तो उन्होंने गर्व से कहा था कि मंत्री-मुख्यमंत्री ही नहीं सरकार है, हमारे विधायक भी सरकार हैं । लोग कहते हैं कि 243 बिहार के पिलर हैं, अगर पिलर को डगमगा रहे हैं तो हमलोग हल्ला करने वाले ही डगमगा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए । समय हो गया ।

श्रीमती ज्योति देवी : इसलिये मैं यही कहना चाहूँगी कि आज बिहार के विकास में सबको हाथ बँटाना चाहिए । एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है और बिहार को इससे और आगे पहुँचाना है । इसी

शुभकामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने के लिए समय दिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श कल दिनांक-03 मार्च, 2023 को भी जारी रहेगा ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-02 मार्च, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 39 (उनचालीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक-03 मार्च, 2023 को 11.00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX - आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।